सुविचार

खुद का अपमान कराके जीने से तो अच्छा मर जाना है क्योंकि प्राणों के त्यागने से केवल एक ही बार कष्ट होता है पर अपमानित होकर जीवित रहने से आजीवन दुःख होता है।

-चाणक्य

हैलो सरकार

जनता की भावनाओं एवं आकांक्षाओं का एकमात्र समाचार-पत्र

पल-पल की टी.वी. एवं रेडियो खबरों के लिए लॉग ऑन करें- www.hellosarkar.com

हैलो सरकार समाचार पत्र में नियमित पाठक बनने, समाचार की प्रति मंगवाने व विज्ञापन देने हेतु सम्पर्क करें
फोन: 0141-2202717
मो: 9214203182
वाट्सप नं. 9928078717

वर्ष-23 | अंक-255 | दैनिक प्रभात संस्करण | जयपुर, मंगलवार 20 मई , 2025 | पृष्ठ-4 | मूल्य: 2.50

प्रचंड गर्मी का कहर

गंगानगर और फलौदी में पारा 46 पार, दिन-रात चल रही है हीट वेव्स

जयपुर। राजस्थान में प्रचंड गर्मी का कहर जारी है। सीमावर्ती जिलों में हालत सबसे ज्यादा खराब है। गंगानगर व फलौदी में अधिकतम तापमान का स्तर 46 डिग्री को भी पार कर गया है। वहीं मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि पश्चिमी राजस्थान में अगले 4 से 5 दिन जबरदस्त हीट वेव्स चलेंगी। राजस्थान में गर्मी का प्रकोप अपने चरम पर है। दिन के साथ रात के समय भी हीट वेव्स झुलसा रही हैं। प्रदेश में अधिकतम तापमान का स्तर 46 डिग्री को भी पार कर गया है। हालांकि अप्रैल के अंत में प्रदेश का पारा 47 डिग्री को छू गया था। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी राजस्थान में अगले 4 से 5 दिनों तक दिन के साथ रात में भी हीट वेव्स चलेंगी। राजधानी जयपुर में भी पारा तेजी से चढ़ रहा है। यहां अधिकतम तापमान 44 डिग्री

को पार कर गया है। प्रशासन की तरफ से शहर की सड़कों पर छिड़काव करवाया जा रहा है। रात्रि के समय भी कई जिलों में पारा 30 डिग्री से अधिक पहुंच गया है। सर्वाधिक न्यूनतम तापमान फलौदी में 316 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं कई अन्य शहरों में भी न्यूनतम तापमान का स्तर 30 डिग्री से अधिक रहा। बीते 24 घंटों में राजस्थान में गंगानगर सबसे गर्म शहर रहा। यहां अधिकतम तापमान 46.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश के चार अन्य शहरों में भी पारा 45 डिग्री से अधिक रहा। वहीं ज्यादातर शहरों में यह 42 से 45 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों में राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र जोधपुर तथा बीकानेर में धूल भरी हवाएं चलेंगी, तथा 20 व 21 मई को यहां मेघगर्जन के साथ बूंदाबांदी भी हो सकती है। वहीं भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में 25 मई तक आंधी और बारिश का दौर चलेगा। सीमावर्ती जिलों में पारा 45 से 46 डिग्री के आसपास रह सकता है।

बीते 24 घंटों में प्रदेश के अधिकतम तापमान की स्थिति इस प्रकार रही। अजमेर में 42.1, भीलवाड़ा में 41.6, अलवर में 43.8, जयपुर में 44, पिलानी में 46.2, कोटा में 44, बाड़मेर में 43, जैसलमेर में 43.8, जोधपुर में 41.6, फलौदी में 43.8, चूरू में 45.8, तथा बीकानेर में 44.4, चूरू में 45.8 व गंगानगर में 46.2 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया।

केंद्र सरकार को साफ करना चाहिए कि भारत-पाकिस्तान के बीच कोई तीसरा व्यक्ति नहीं चाहिए-अशोक गहलोत

जयपुर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत-पाकिस्तान मध्यस्थता की पेशकश को स्पष्ट रूप से खारिज करना चाहिए था। उन्होंने सरकार पर डैमेज कंट्रोल के लिए तिरंगा यात्रा निकालने का आरोप लगाया।

अशोक गहलोत ने कहा, सरकार यह मानने को तैयार नहीं कि उससे गलती हुई। ट्रंप होते कौन हैं बीच में बोलने वाले? सरकार को कहना चाहिए था कि भारत-पाकिस्तान के बीच कोई तीसरा व्यक्ति नहीं चाहिए। अब ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने मध्यस्थता कराई,ऐसे में कौन सच बोल रहा है? सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। यह मामला देश की संप्रभुता से जुड़ा है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता।

इसके अलावा, गहलोत ने विदेश में पाकिस्तान को बेनकाब

करने और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देने जा रहे संसदों के प्रतिनिधिमंडल के लिए सांसदों के चयन को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने जानबूझकर विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश की। गहलोत ने कहा, फ्रकांग्रेस ने चार सांसदों के नाम भेजे थे, लेकिन सरकार ने दावा किया कि उसने नाम मांगे ही नहीं। फिर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन क्यों किया? यह साफ दिखाता है कि भाजपा ने शरारत की और चार नए नाम चुन लिए। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी के जो चार सांसद जो चुने गए हैं, वे अपनी भूमिका शानदार तरीके से निभाएंगे।

गहलोत ने शशि थरूर के मामले पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, थरूर अनुभवी नेता हैं, पूर्व विदेश राज्य मंत्री रह चुके हैं और पार्टी उनका सम्मान करती है। लेकिन, थरूर को सरकार के ऑफर पर पार्टी हाईकमान से सलाह लेनी चाहिए थी। अगर थरूर ने कह दिया होता कि वे हाईकमान से बात करेंगे, तो यह विवाद ही नहीं उठता। उनकी गलती थी, लेकिन भाजपा की शरारत भी सबके सामने है।

गहलोत ने आगे कहा कि इस तरह के मामलों में विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश अच्छी परंपरा नहीं है। पहलगाम जैसे मामलों के बाद देश एकजुट हुआ था, लेकिन भाजपा ऐसी हरकतों से बाज नहीं आती। सरकार को पारदर्शी और जवाबदेह होना होगा, ताकि देश की जनता के सामने सच्चाई आ सके। पार्टी इस मुद्दे को जनता के सामने ले जाएगी और सरकार की नाकामियों को उजागर करेगी।

झोटवाड़ा में 25 मई को निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा

जयपुर। राजस्थान सरकार में सैनिक कल्याण मंत्री और झोटवाड़ा से लोकप्रिय विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के मार्गदर्शन में 25 मई 2025 को झोटवाड़ा में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। यह यात्रा हाल ही में भारतीय सेना द्वारा अंजाम दिए गए %ऑपरेशन सिंदूर% में देश की रक्षा करते हुए पराक्रम दिखाने वाले वीर जवानों को समर्पित होगी। इस आयोजन के माध्यम से भारतीय सेना की बहादुरी, राष्ट्रप्रेम और बलिदान की भावना को आमजन तक पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा। तिरंगा यात्रा की तैयारियों को लेकर कर्नल राठौड़ ने भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कर्मठ कार्यकर्ताओं के साथ एक सकारात्मक संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य रणनीति और वीरता का जीवंत प्रमाण है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को नष्ट कर यह दिखा दिया कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए हर चुनौती का जवाब देने में सक्षम है। यह अभियान हर देशवासी के लिए गर्व का विषय है। कर्नल राठौड़ ने कहा कि झोटवाड़ा में आयोजित होने वाली तिरंगा यात्रा न केवल सेना के शौर्य को सम्मान देने का प्रतीक बनेगी, बल्कि यह युवाओं और बच्चों को भी देशप्रेम की भावना से जोड़ने का सशक्त माध्यम होगी। उन्होंने कहा कि आज के दौर में जरूरी है कि युवा वर्ग केवल सोशल मीडिया तक सीमित न रहे, बल्कि वह देश की विरासत, बलिदान और सैनिकों के संघर्ष को जाने और उसका सम्मान करे। तिरंगा यात्रा के माध्यम से झोटवाड़ा की गलियों में देशभक्ति की गूंज सुनाई देगी। स्थानीय लोग, युवाओं के साथ स्कूली बच्चे, महिलाएं, पूर्व सैनिक और समाज के अन्य वर्गों के लोग इस यात्रा में हिस्सा लेंगे। यह यात्रा भारत माता की जय और वंदे मातरम् के नारों के साथ झंडा लेकर निकलने वाली एक ऐसी प्रेरणादायक पहल होगी जो आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र के प्रति कर्तव्य और समर्पण की भावना से जोड़ने का काम करेगी।

कुल मिलाकर, 25 मई को झोटवाड़ा का माहौल पूरी तरह देशभक्ति में रंगा होगा और यह तिरंगा यात्रा भारत की सैन्य ताकत, गौरव और नागरिकों की एकता का प्रतीक बनेगी। कर्नल राठौड़ के नेतृत्व में यह आयोजन न केवल क्षेत्र में उत्साह और गर्व का संचार करेगा, बल्कि पूरे प्रदेश में एक सकारात्मक संदेश भी देगा।

भ्रष्टाचार के मामले में सख्त दिखे भजनलाल, SDO-सहित चार अफसरों पर कार्रवाई

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार के मामलों पर सख्ती दिखाते हुए सोमवार को चार प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई की। मुख्यमंत्री निवास पर हुई विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान रायपुर (ब्यावर) के एसडीओ को सस्पेंड कर दिया गया, जबकि रामसर (बाड़मेर) के एसडीएम को एपीओ किया गया है। इसके साथ ही दोनों स्थानों - रायपुर (ब्यावर) और रामसर (बाड़मेर) के तहसीलदारों को भी एपीओ किया गया है।

बैठक में जब भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जानकारी सामने आई तो मुख्यमंत्री ने तत्काल संज्ञान लेते हुए यह निर्णय लिया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में यह बैठक मुख्यमंत्री

निवास पर आयोजित हुई थी, जिसमें राज्य के विभिन्न विभागों की योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। बैठक में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (ह्स्न्न्) में आवेदनों की स्थिति, कार्मिकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लंबित मामले, बजट घोषणाओं की क्रियान्विति, भूमि आवंटन, जनसुनवाई, और अवैध खनन जैसे विषयों पर गहन चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि शासन की योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सर्वोपरि है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता से जुड़ी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक शीघ्र पहुंचे, और किसी भी स्तर पर लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में तुरंत कार्रवाई की मिसाल पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने अफसरों को चेताया कि भविष्य में भी ऐसी किसी शिकायत पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जयपुर के कानोता में जमीन विवाद ने पकड़ा तूल, पथराव-तोड़फोड़ और बंदूक तानने तक पहुंचा मामला

जयपुर । जयपुर के कानोता थाना इलाके की हनुमान वाटिका कॉलोनी में रविवार दोपहर जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दो पक्षों के बीच हुए विवाद में जमकर पथराव हुआ और कॉलोनी में खड़ी कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। इसी दौरान एक पक्ष द्वारा बंदूक तानने की घटना भी सामने आई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाना प्रभारी हिम्मत सिंह ने बताया कि विवाद उदय सिंह गुर्जर (सेना से रिटायर्ड) और सौरभ मीना के बीच जमीन को लेकर हुआ। दोनों ने एक-दूसरे की जमीन पर कब्जा जताया और निर्माण को लेकर आपत्ति जताई। आरोप है कि उदय सिंह ने कॉलोनी की एंट्री पर गेट लगा दिया, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी होने लगी।

इतिहास और वीरता को लेकर हो रही बयानबाज़ी पर सियासी घमासान

नागौर सांसद और RLP प्रमुख हनुमान बेनीवाल के इतिहास को लेकर दिए हालिया विवादित बयान पर अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राठौड़ ने बेनीवाल को 'कुंठित मानसिकता; वाला बताते हुए उन्हें राजस्थान का गौरवशाली इतिहास पढ़ने की सलाह दी है।

दरअसल, जयपुर में स्ढ्ढ भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे बेनीवाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि राजस्थान में एक-दो लोगों ने ही लड़ाइयां लड़ीं, बाकी तो मुगलों के आगे दंडवत हो जाते थे, मुगलों के आने पर 70 किलोमीटर पहले ही अपनी बेटियां लेकर पुहंच जाते थे। कुछ तो अपनी बेटियों को भी आगे कर देते थे। उन्होंने केवल महाराणा प्रताप और राजा सूरजमल को ही असली योद्धा बताया था। इस बयान के बाद सामाजिक और राजनीतिक लोगों ने बेनीवाल पर निशाना साधा है।

बेनीवाल को मदन राठौड़ की दो टूक

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बेनीवाल के बयान की निंदा करते हुए कहा कि यदि इतिहास पढ़ेंगे तो राणा सांगा, राणा कुम्भा, पृथ्वीराज चौहान, अमरसिंह

राठौड़, दुर्गादास राठौड़ जैसे वीर योद्धा मिलेंगे। लेकिन पढ़ेंगे कब? उन्हें तो मेरी-तेरी करने से ही फुर्सत नहीं मिलती। राठौड़ ने बेनीवाल के बयान को राजस्थान की वीर परंपरा का अपमान बताते हुए कहा कि यह न सिर्फ इतिहास का अपमान है, बल्कि देश की चेतना पर भी चोट है।

वहीं एक अन्य बयान में मदन राठौड़ ने कांग्रेस सांसद जयराम रमेश पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे सैन्य अभियान की सफलता देश की बड़ी उपलब्धि है। इसे दुनिया में बताने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजा जा रहा है। कांग्रेस को इसका विरोध नहीं करना चाहिए।

राजपूत सभा ने भी जताया आक्रोश

मारवाड़ राजपूत सभा के अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगटा ने भी बेनीवाल के बयान पर तीखा विरोध जताते हुए कहा कि ऐसे ओछी सोच वाले व्यक्ति का दिमागी दिवालियापन साफ नज़र आता है। यदि राजस्थान के वीर नहीं होते, तो आज बहुत कुछ अलग होता। उन्होंने बेनीवाल पर परदे के पीछे समझौते और सौदेबाजी करने का भी आरोप लगाया।

इधरस बेनीवाल के बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है। यूजर्स ने उन्हें इतिहास पढ़ने की सलाह देते हुए कहा कि राजस्थान की धरती वीरों की जननी है, उसका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री का अलवर दौरा-महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण

अलवर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को अलवर पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया और किसानों से संवाद किया। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर अलवर के केंद्रीय विद्यालय में बनाए गए हेलीपैड पर उतरा, जहां लोगों ने गुलाब का फूल भेंट कर उनका स्वागत किया। इस दौरान ड्रोन से पुष्प वर्षा भी की गई।

महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण

तय कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री सबसे पहले मोती डूंगरी पहुंचे, जहां उन्होंने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा 2200 किलो वजनी है और 12.30 फीट की ऊंचाई पर स्थापित की गई है। इसकी निर्माण लागत करीब 50 लाख रुपये बताई गई है। मूर्ति 85त्न तांबा

और 15त्न जिंक से बनी हुई है।

मुख्यमंत्री का श्वेत क्रांति 2.0 कार्यक्रम में संबोधन

इसके पश्चात मुख्यमंत्री श्वेत क्रांति 2.0 कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अलवर सरस डेयरी ग्राउंड पहुंचे, जहां उन्होंने किसान और पशुपालक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा हमने किसान की खुशहाली के लिए काम किया है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर किसानों के लिए योजनाएं बना रही हैं।

कांग्रेस सरकार पर उठाए सवाल

मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने सबसे ज्यादा शासन किया, लेकिन किसानों के लिए क्या किया? उन्होंने दावा किया कि पूरे देश में राजस्थान में सबसे अधिक एमएसपी पर गेहूं की खरीद हो रही है। सीएम शर्मा ने गोपालक ऋष्ण योजना की जानकारी भी साझा की और कहा कि अब किसानों को दिन में बिजली मिल रही है, जबकि पहले उन्हें रात में बिजली मिलती थी।

पेपर लीक और पहलगाम हमले पर बोले

उन्होंने पेपर लीक के मुद्दे पर भी बात की और कहा कि दोषियों को जेल भेजा गया है। साथ ही हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में सेना की कार्रवाई की सराहना की और कहा कि आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता सिर्फ ट्वीट करते हैं, जबकि प्रधानमंत्री जो कहते हैं, वो करके दिखाते हैं। डबल इंजन की सरकार किसानों और महिलाओं का सशक्तिकरण कर रही है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ मंच पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम, वनमंत्री संजय शर्मा, विधायक बालकनाथ, देवी सिंह शेखावत, सुखवंत सिंह, जसवंत यादव सहित कई नेता मौजूद रहे।

नगर निगम ग्रेटर की सख़्ती-8 केन्टर और 2 ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त, अतिक्रमणकारियों से वसूला कैरिंग चार्ज

सतर्कता शाखा की टीम ने मानसरोवर के रीको काँटा चौराहे, जगतपुरा के 7 नंबर चौराहे से अक्षय पात्र चौराहा, जगतपुरा पुलिया से केपिटल मॉल तक और इंदिरा गांधी नगर सेक्टर-3 जैसे इलाकों में फैले अस्थाई अतिक्रमण को हटाया।

जयपुर। नगर निगम ग्रेटर की सतर्कता शाखा ने सोमवार को अस्थाई अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए 59 हजार रुपये का कैरिंग चार्ज वसूल किया। इस अभियान के तहत 8 केन्टर और 2 ट्रैक्टर-ट्रॉली सामान जब्त कर गोदाम में भेजा गया।

यह कार्रवाई नगर निगम ग्रेटर की आयुक्त रूकमणि रियाड़ के

निर्देश पर उपायुक्त सतर्कता अजय कुमार शर्मा के नेतृत्व में की गई। सतर्कता शाखा की टीम ने मानसरोवर के रीको काँटा चौराहे, जगतपुरा के 7 नंबर चौराहे से अक्षय पात्र चौराहा, जगतपुरा पुलिया से केपिटल मॉल तक और इंदिरा गांधी नगर सेक्टर-3 जैसे इलाकों में फैले अस्थाई अतिक्रमण को हटाया।

उपायुक्त अजय कुमार शर्मा ने बताया कि जिन स्थानों से अतिक्रमण हटाया गया, वहां अस्थाई रूप से ठेलों और फेरी वालों द्वारा सड़क किनारे सामान लगाया गया था, जिससे यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही थी और आमजन को परेशानी हो रही थी। टीम ने मौके पर मौजूद अतिक्रमणकारियों को समझाइश भी दी और चेतावनी दी गई कि भविष्य में यदि अतिक्रमण पाया गया तो भारी जुर्माना और कठोर कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम की इस कार्यवाही को स्थानीय लोगों ने सराहा है। निगम का कहना है कि शहर में यातायात व्यवस्था और सार्वजनिक स्थानों की सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे।ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

राजस्थान में सबसे ज्यादा अवैध बांग्लादेशी नागरिक सीकर में हुए चिन्हित, 148 को वापस भेजा गय

जयपुर। केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश के बाद से राजस्थान में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की धरपकड़ जारी है । राजस्थान के गृह विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक 15 मई 2025 तक 17 जिलों में कुल 1001 अवैध बांग्लादेशी चिन्हित किए जा चुके है, जिसमें से 14 मई को 148 अवैध बांग्लादेशियों को जोधपुर एयरपोर्ट से हवाई जहाज के जरिये प्रत्यावर्तित किया जा चुका है।

गृह विभाग के मुताबिक जयपुर पूर्व में 109, जयपुर उत्तर में 37, जयपुर पश्चिम में 43, जयपुर ग्रामीण में 29, अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को चिन्हित किया जा चुका है, जबकि सीकर में 394 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को चिन्हित किया गया है । वहीं कोटपूतली-बहरोड़ नीमराणा में कुल 114, अलवर में 117 अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए है । जबकि भिवाड़ी में 67, सलूम्बर में 27, झुंझुनूं में 35, दौसा में 5, करौली में 3, अजमेर में 12, बीकानेर में 2, कोटा ग्रामीण में 2, डीडवाना-कुचामन में 4 और पाली में एक बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा गया है ।

कुल 1001 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों में से 376 पुरुष है, जबकि 284 महिलाएं है, वहीं 341 बच्चों की संख्या है । इनमे से 973 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों का डाटा एफआईपी पोर्टल पर डाटा अपलोड किया जा चुका है । इन सभी को डिटेन सेंटर में रखा गया है ।

नेताओं के बिगड़े बोल से आहत होती राष्ट्रीयता

नफरती सोच एवं हेट स्पीच का बाजार बहुत गर्म है। राजनीति की सोच ही दूषित एवं घृणित हो गयी है। नियंत्रण और अनुशासन के बिना राजनीतिक शुचिता एवं आदर्श राजनीतिक मूल्यों की कल्पना नहीं की जा सकती। नीतिगत नियंत्रण या अनुशासन लाने के लिए आवश्यक है सर्वोपरि राजनीतिक स्तर पर आदर्श स्थिति हो, अनुशासन एवं संयम हो, तो नियंत्रण सभी स्तर पर स्वयं रहेगा और इसी से देश एक आदर्श लोकतंत्र को स्थापित करने में सक्षम हो सकेगा। युद्ध जैसे माहौल में सेना एवं उसके नायकों का मनोबल बढ़ाने की बजाय उनके साहस एवं पराक्रम पर छींटाकशी करना दुर्भाग्यपूर्ण है।

(लेखक - ललित गर्ग)

सेना के शौर्य पर सम्मान की बजाय अपमान के बिगड़े बोल को लेकर राजनीतिक घमासान छिड़ जाना स्वाभाविक है। कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के संबंध में क्रमशः मंत्री विजय शाह और सपा महासचिव राम गोपाल यादव द्वारा की गई टिप्पणियों पर राजनीतिक विवाद और कानूनी कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। बड़ा प्रश्न है कि क्या धर्म और जाति के नाम पर वोट के लिए सेना और सेना से जुड़ी बेटियों के सम्मान को चोट पहुंचाई जाना उचित है? चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष वाणी का संयम अपेक्षित है। भारतीय राजनीति में बिगड़े बोल, असंयमित भाषा एवं कड़ावपन की मानसिकता चिन्ताजनक है। ऐसा लगता है ऊपर से नीचे तक सड़कछाप भाषा ने अपनी बड़ी जगह बना ली है। यह ऐसा समय है जब शब्द सहमे हुए हैं, क्योंकि उनके दुरूपयोग की घटनाएं लगातार जारी हैं।

जब देश पहलगाम की त्रासद घटना एवं उसके बाद पाकिस्तान से बदला लेने की शौर्य की महत्वपूर्ण घटना के मोड़ पर खड़ा है, तब कुछ नेताओं के बिगड़े बोल बहुत दुखद और निंदनीय हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के एक मंत्री विजय शाह एवं समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। विजय शाह को राज्य मंत्रिमंडल से हटाने की मांग तेज हो गई है। कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विजय शाह की विवादास्पद टिप्पणी एक ऐसा दाग है, जिसे आसानी से नजरंदाज नहीं किया जा सकता। यह मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा और मामला भी दर्ज हो गया, तो आश्चर्य नहीं । देश के नेताओं व मंत्रियों को ऐसी हल्की और स्तरहीन बातों से परहेज करना चाहिए।

नफरती सोच एवं हेट स्पीच का बाजार बहुत गर्म है। राजनीति की सोच ही दूषित एवं घृणित हो गयी है। नियंत्रण और अनुशासन के बिना राजनीतिक शुचिता एवं आदर्श राजनीतिक मूल्यों की कल्पना नहीं की जा सकती। नीतिगत नियंत्रण या अनुशासन लाने के लिए आवश्यक है सर्वोपरि राजनीतिक स्तर पर आदर्श स्थिति हो, अनुशासन एवं संयम हो, तो नियंत्रण सभी स्तर पर स्वयं रहेगा और इसी से देश एक आदर्श लोकतंत्र को स्थापित करने में सक्षम हो सकेगा। युद्ध जैसे माहौल में सेना एवं उसके नायकों का मनोबल बढ़ाने की बजाय उनके साहस एवं पराक्रम पर छींटाकशी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। चर्चा में बने रहने के लिए ही सही, राजनेताओं के विवादित बयान गाहे-बगाहे सामने आ ही जाते हैं, लेकिन ऐसे बयान एक ऐसा परिवेश निर्मित करते हैं जिससे राजनेताओं एवं राजनीति के लिये घृणा पनपती है। यह सही है कि शब्द आवाज नहीं करते, पर इनके घाव बहुत गहरे होते हैं और इनका असर भी दूर तक पहुंचता है और देर तक रहता है। इस बात को राजनेता भी अच्छी तरह जानते हैं इसके बावजूद जुबान से जहरीले बोल सामने आते ही रहते हैं।

यह चिंताजनक है कि इधर के वर्षों में कुछ भी बयान दे देने की बुरी आदत बढ़ रही है। बिगड़े बोल वाले नेता बेलगाम हो रहे हैं। कोई दो राय नहीं कि पहले राजनीतिक दलों और उसके बाद सरकारों को इस मोर्चे पर अनुशासन एवं वाणी संयम का बांध बांधना चाहिए । विजय शाह करीब आठ बार चुनाव जीत चुके हैं, मतलब, अनुभवी नेता हैं, तो क्या वह चर्चा में रहने के लिए बिगड़े बोल का सहारा लेते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में खिंचाई के बाद अब वह सफाई देने में लगे हैं। उन्होंने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा है कि उनकी टिप्पणियों को संदर्भ से बाहर ले जाया गया और उनका मकसद कर्नल कुरैशी की बहादुरी की प्रशंसा करना था। उन्होंने यह भी कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी मेरी सगी बहन से भी बढ़कर हैं। वह माफी भी मांग रहे हैं, तो साफ है कि उनका पद खतरे में है। अगर वह पहले ही सावधानी बरतते या गलती होते ही माफी मांग लेते, तो मामला इतना नहीं बढ़ता। विजय शाह का मामला थमा भी नहीं है कि मध्य प्रदेश के ही उप- मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने भी बिगड़े बोल को अंजाम दे दिया है। उनका मानना है कि देश की सेना प्रधानमंत्री के सामने नतमस्तक है। वास्तव में, ऐसी गलतबयानी से किसी के भी सम्मान में वृद्धि नहीं होती है। देश अभी-अभी एक संघर्ष से निकला है। यह एकजुटता और परस्पर समन्वय बढ़ाने के लिए संभलकर बोलने का समय है। राष्ट्रीय एकता एवं राजनीतिक ताने-बाने को ध्वस्त कर रहे जहरीले बोल की समस्या दिन-प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है।

संकीर्णता एवं राजनीति का उन्माद एवं 'हेट स्पीच' के कारण न केवल विकास बाधित हो रहा है, सेना का मनोबल प्रभावित हो रहा है, बल्कि देश की एकता एवं अखण्डता भी खण्ड-खण्ड होने के कगार पर पहुंच गयी है। राजनेताओं के नफरती, उन्मादी, द्वेषमूलक और भड़काऊ बोलों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने भी कड़ी टिप्पणियां की है। भाषा की मर्यादा सभी स्तर पर होनी चाहिए। कई बार आवेश में या अपनी बात कहने के चक्कर में शब्दों के चयन के स्तर पर कमी हो जाती है और इसका घातक परिणाम होता है। मुद्दों, मामलों और समस्याओं पर बात करने की बजाय जब नेता एक-दूसरे पर निजी हमले करने लगें तो यह उनकी हताशा, निराशा और कुंठा का ही परिचायक होता है। यह आज के अनेक नेताओं की आदत सी बन गई है कि एक गलती या झूठ छिपाने के लिए वे गलतियों और झूठ का अंबार लगा देते हैं। क्या यह सत्ता का अहंकार एवं नशा है? संसद में गलती एक बार अटल बिहारी वाजपेयी से भी हुई थी, उन्होंने तत्काल सुधार करते हुए कहा था कि चमड़े की जुबान है, फिसल जाती है। बेशक, अच्छा नेता वही होता है, जो गलतियां नहीं करता और अगर गलती हो जाए, तो तत्काल सुधारता है।

जिम्मेदार पदों पर बैठे नेताओं को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनके अच्छे-बुरे बोल व गलत-सही कारनामे इतिहास में दर्ज हो रहे हैं। ध्यान रखना होगा, पहले केवल शब्द वायरल होते हैं, पर अब शब्द के साथ वीडियो भी वायरल होता है। ध्यान रहे, समय के साथ मीडिया का बहुत विस्तार हुआ है और उसका एक बड़ा हिस्सा ऐसी ही गलतबयानी का भूखा है। उसे ऐसे ही बिगड़े बोल वाले कंटेंट की तलाश है। अतः कम से कम देश के जिम्मेदार दलों के नेताओं को कोई भी राष्ट्र-विरोधी अप्रिय या प्रतिकूल ध्वनि नहीं पैदा करनी चाहिए। अनेक राजनीतिक दलों के नेता ऐसे वक्तव्य देते हैं और विवाद बढ़ता देख बाद में सफाई देने से भी नहीं चूकते। वोट के लिए धर्म, सम्प्रदाय, जाति, समाज किसी को भी नहीं छोड़ा जा रहा। पार्टी कोई सी भी हो, नेता अपने विरोधियों के खिलाफ जहर उगलने से नहीं चूकते लेकिन सेना नायकों पर टिप्पणियां बहुत ही घातक है।

नेता चाहे सत्ता पक्ष से जुड़े हों या प्रतिपक्ष से, अक्सर वाणी असंयम एवं बिगड़े बोल में हदें पार कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के समय-समय पर दिए गए निर्देशों की भी इन्हें परवाह नहीं है। पूरे विश्व में आज जब हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, तो देश के भीतर और देश के बाहर बैठी 'भारत विरोधी शक्तियां' एकजुट होकर राष्ट्रीय एकता एवं लोकतांत्रित मूल्यों के ताने-बाने को क्षत-विक्षित करना चाहती है। ऐसी शक्तियां किसी भी तरह भारत से विकास का एक कालखंड छीन लेना चाहती हैं। उन्हें नेताओं के बिगड़े बोलों से ऊर्जा मिलती है। सोचने की बात तो यह है कि राजनीतिक भावनाओं एवं नफरती सोच को प्रश्रय देने वाले नेताओं का भविष्य भी खतरे से खाली नहीं हैं। उनका भविष्य कालिमापूर्ण है। उनकी नफरती कोशिशों पर देश एवं दुनिया की नजरे टिकी हैं। वे क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, इसी से भारतीय लोकतंत्र की गरिमा दुनिया में बढ़ सकती है। जरूरत है कि हमारे राजनीति दल अपनी सोच को परिपक्व बनाये, मतभेदों को स्वीकारते हुए मनभेद को न पनपने दे।

卐राजनीतिक सिस्टम卐 की रोग मुक्ति, स्वस्थ समाज एवं राष्ट्र का आधार होगा। राष्ट्रीय चरित्र एवं राजनीतिक चरित्र निर्माण के लिए नेताओं एवं उनके दलों को आचार संहिता से बांधना ही होगा। अब तो ऐसा भी महसूस होने लगा है कि देश की दंड व्यवस्था के तहत जहां 'हेट स्पीच' या बिगड़े बोल को नये सिरे से परिभाषित करने की आवश्यकता है वहीं इस समस्या से निपटने के लिए 'हेट स्पीच' एवं बिगड़े बोल को अलग अपराध की श्रेणी में रखने के लिए कानून में संशोधन का भी वक्त आ गया है?

(लेखक, पत्रकार, स्तंभकार)

(यह लेखक के व्य क्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अ निवार्य नहीं है)

संपादकीय

फुटपाथ का साथ

सड़क पर तेज रफ्तार दौड़ती कारों और अतिक्रमण की भेंट चढ़े फुटपाथों पर पैदल यात्रियों का चलना अब दुश्वार हो चला है। यही वजह है कि बुजुर्ग लोग सड़कों पर आने से डरते हैं और घरों तक सिमटकर रह जाते हैं। वे फुटपाथ न होने के कारण सड़कों पर चलते हैं और अनियंत्रित गति वाले वाहनों के शिकार हो जाते हैं। अदालत में दिए गए एक आंकड़े के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले करीब बीस फीसदी लोग पैदल यात्री होते हैं। इन हालात में दिव्यांग लोग कैसे सड़कों पर निकल सकते हैं, ये कल्पना से परे है। देश के करोड़ों मूक पैदल यात्रियों को आवाज देने के मकसद से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति ए.एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने सख्त लहजे में कहा कि फुटपाथ की सुविधा लोगों का संवैधानिक अधिकार है। पीठ ने केंद्र व राज्यों को कहा कि दो महीने में सुनिश्चत करें शहरों व गांवों में पैदल चलने वालों के लिये साफ, अतिक्रमण मुक्त और दिव्यांगों के अनुकूल फुटपाथ उपलब्ध हों। सभी सार्वजनिक सड़कों पर उपयुक्त फुटपाथ बनाना और उनसे अतिक्रमण हटाना अनिवार्य है। कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकारों से कहा कि वे बताएं पैदल यात्रियों के अधिकारों की रक्षा के लिए उसके पास क्या नीति है। कोर्ट ने दो महीने में रिपोर्ट देने को कहा है। शीर्ष अदालत ने मुंबई हाईकोर्ट की ओर से पहले से जारी दिशा-निर्देशों को आदर्श मानते हुए अन्य राज्यों से इसे अपनाने को कहा। दरअसल, कोर्ट भी इस बात से सहमत दिखा कि जब फुटपाथ नहीं होते तो गरीब, बुजुर्ग,बच्चे और दिव्यांगजन मजबूरी में सड़कों पर चलते हैं। वे भीड़भाड़ में हादसों का शिकार हो जाते हैं। अदालत ने कहा कि यह केवल यातायात का मुद्दा नहीं है,यह जीवन का अधिकार है। ये उन करोड़ों भारतीयों के लिए एक उम्मीद है जो जान जोखिम में डालकर सड़कों पर चलते हैं। अब हर कदम पर सुरक्षित और जीवन की अहमियत होनी चाहिए। निस्संदेह, देश में फुटपाथों की दुर्दशा, अतिक्रमण और दिव्यांगों की लाचारी किसी से छिपी नहीं है। अकेले वर्ष 2022 में 77 हजार पैदल यात्रियों के साथ हुई दुर्घटना में करीब 32,797 की मृत्यु हुई और 34 हजार गंभीर रूप से घायल हुए। निस्संदेह, कोर्ट ने पैदल चलने वाली करोड़ों की मूक बिरादरी को संवैधानिक आवाज देने देने की सार्थक पहल की है। विडंबना यह है कि देश की राजधानी दिल्ली में अस्सी फीसदी पैदल मार्गों पर रेहड़ी-पटरी वालों, दुकानदारों व गाड़ी वालों ने कब्जा कर रखा है। इस वर्ष हर माह करीब 48 पदयात्री सड़क दुर्घटना में मारे गए। यही वजह है कोर्ट ने फुटपाथ को संवैधानिक अधिकार बताते हुए इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीशुदा बताया। जिसे केंद्र व राज्य सरकारों को पैदल यात्रियों के लिये इसे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन के लिए सिर्फ छह माह का समय दिया है।

पहलगाम त्रासदी : नफरत की तेज़ होती आंधी

(लेखक - राम पुनियानी)

पहलगाम के पास बैसरन में 26 पर्यटकों की हत्या हाल के समय की सबसे भीषण त्रासदियों में से एक है। बैसरन एक अत्यंत रमणीक स्थान है जहां सिर्फ घोड़े पर सवार होकर या ऊबड़-खाबड़ रास्ते पर पैदल चलकर पहुंचा जा सकता है। इस हत्याकांड से सारा देश गहन शोक में डूब गया। यद्यपि आतंकवादियों ने पर्यटकों की हत्या उनके धर्म की पहचान करके की थी, लेकिन हमले का शिकार होने वालों में एक स्थानीय मुसलमान घोड़े वाला, जो पर्यटकों के साथ आया था, भी था। वह तब मारा गया जब उसने आतंकियों का विरोध किया। कश्मीरी कुलियों ने पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया और कश्मीरियों ने अपने घरों और मस्जिदों के दरवाजे मेहमानों के लिए खोल दिए। कश्मीर में बंद का आयोजन किया गया और 'हिंदू मुस्लिम एकता' का संदेश देने वाले कई जुलूस निकाले गए। सारे देश में मुसलमानों और अन्यों ने मोमबत्ती जुलूस निकाले और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लगभग इन्हीं तारीखों में मोदीजी की कश्मीर यात्रा तय की गई थी। लेकिन निर्धारित तिथि के कुछ ही दिन पहले उसे रद्द कर दिया गया। घटना के समय वे सऊदी अरब में थे। घटना के बाद वे अपनी यात्रा अधूरी छोड़कर स्वदेश रवाना हो गए। किंतु वापिस अपने के बाद कश्मीर जाने के बजाए वे एक चुनावी रैली में भाग लेने के लिए बिहार चले गए जहां उन्होंने आतंकियों को अंग्रेजी में कड़ी चेतावनी दी। आतंकी मुसलमान थे और मारे गए लोग हिंदू थे। इसे दबे-छिपे ढंग से इस घटना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बना दिया गया।

डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम की घोषणा की। मोदीजी ने इस बारे में कुछ अलग बात कही। इस बीच गोदी मीडिया की बन आई और उसने नफरत फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वे अपने शानदार आरामदायक स्टूडियो में बैठे-बैठे पाकिस्तान के विभिन्न शहरों पर भारतीय सेना का कब्जा होने की खबरें देते रहे। गोदी मीडिया अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गया और उसने पत्रकारिता की आचार संहिता के उल्लंघन का नया रिकार्ड कायम किया, जिसे वह बहुत पहले ताक पर रख चुका है।

इस सबका सबसे बुरा नतीजा मुसलमानों के प्रति नफरत में बढ़ोत्तरी के रूप में सामने आया। सारा देश इस्लामोफोबिया के सैलाब में डूब गया और इसकी तीव्रता और स्तर अकल्पनीय ऊंचाई तक पहुंच गए। लातूर में एक मुसलमान पर पाकिस्तानी होने का लेबिल चस्पा कर उसकी बुरी तरह पिटाई गई। उसे इतना अपमान महसूस हुआ कि उसने आत्महत्या कर ली। उत्तराखंड के एक हॉस्टल में कश्मीरी छात्रों को आधी रात को बाहर निकाल दिया गया और उन्हें देहरादून विमानतल के बाहर रात बितानी पड़ी। सबसे बुरी हरकत मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार के मंत्री विजय शाह ने की। उन्होंने भारतीय सेना की प्रवक्ता कर्नल सोफिया कुरैशी को 'आतंकवादियों की बहन' बताया। बाद में बात संभालने के लिए उन्होंने माफी मांग ली। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसायटी एंड सेक्यूलरिज्म, मुंबई की मिथिला राऊत ने दैनिक लोकसत्ता (मराठी) में प्रकाशित अपने एक लेख में विभिन्न समाचारपत्रों में छपी खबरों के आधार पर मुसलमानों के खिलाफ हुई नफरत-जनित हरकतों की जानकारी प्रस्तुत की है। उनके लेख के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद कई मुस्लिम विरोधी घटनाएं हुईं। ऐसी शर्मनाक घटनाओं में से एक उत्तरप्रदेश के शामली के ठोडा गांव में हुई जहां गोविंद ने सरफराज पर हमला किया। गोविंद ने कहा कि तुमने हमारे 26 मारे हम भी तुम्हारे 26 मारेंगे! पंजाब के डेरा बस्सी में यूनिवर्सल समूह के छात्रावास में कश्मीरी छात्रों पर हमला किया गया। मसूरी में रहने वाले शब्बीर धर नाम के एक कश्मीरी, जो शाल बेचते थे, और उनके सहायक पर हमला किया गया और उन्हें पहलगाम की हत्याओं का कुसूरवार बताते हुए धमकाया गया कि यदि वे दुबारा वहां नजर आए तो बहुत बुरा होगा। हरियाणा के रोहतक नाम के गांव में मुस्लिम निवासियों को धमकाया गया और उनसे 2 मई तक गांव छोड़ देने के लिए कहा गया।

ये तो केवल कुछ घटनाएं हैं जिनका विवरण समाचारपत्रों से पता लगा है। लेकिन इनसे यह साफ जाहिर है कि नफरत किस हद तक बढ़ गई है। समाज में माहौल धीरे-धीरे खराब हो रहा है। हिंदू दक्षिणपंथियों ने पहले से ही मुस्लिम विरोधी वातावरण बनाया हुआ है। शुरूआत में आरएसएस शाखाओं में मध्यकालीन इतिहास को तोड़-मरोड़ कर मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाई गयी। हाल के कुछ सालों में गोदी मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए मुसलमानों की शत्रु की छवि बनाई गई। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान के निर्माण से साम्प्रदायिक राजनीति करने वालों को एक नया हथियार मिल गया और उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान बनने के लिए मुसलमान जिम्मेदार हैं। यह पूरी तरह से इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश करने वाली बात थी क्योंकि पाकिस्तान के निर्माण की तीन वजहें थीं - अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति, मुस्लिम साम्प्रदायिकता और हिन्दू साम्प्रदायिकता। द्विराष्ट्र सिद्धांत सबसे पहले हिन्दुत्ववादी विचारक विनायक दामोदर सावरकर ने पेश किया था।

पाकिस्तान बनने के बाद यह प्रोपेगेंडा कि पाकिस्तान के निर्माण के लिए मुसलमान जिम्मेदार हैं, नफरत फैलाने का एक नया औजार बन गया। हकीकत यह है कि दो देश, भारत और पाकिस्तान एक साथ बने थे। मुस्लिम बहुल इलाके पाकिस्तान का हिस्सा बने। मुस्लिम-विरोधी प्रोपेगेंडा का एक नया मुद्दा बन गया कश्मीर का पेंचीदा मामला। 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों के कश्मीर से पलायन का इस्तेमाल भी मुसलमानों खिलाफ किया गया। जब यह पलायन हुआ था तब भाजपा समर्थित वी। पी। सिंह सरकार केन्द्र में सत्ता में थी और भाजपा की विचारधारा वाले जगमोहन कश्मीर के राज्यपाल थे। इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए मुसलमानों को पंडितों के पलायन की मुख्य वजह बताते हुए उनके प्रति घृणा को और बढ़ाया गया। इस तरह एक के बाद एक कई मसलों का इस्तेमाल भारतीय मुसलमानों को सताने के लिए किया गया। इन दिनों भाईचारे की बातें बहुत कम सुनायी पढ़ती हैं और हर घटना का इस्तेमाल मुसलमानों के प्रति पहले व्याप्त नफरत को और बढ़ाने के लिए किया जाता है।

(चिंतन-मनन)

चिंतन मनन

अकर्मण्य न बनें

एक कहानी है। एक राजा था। उसे मंत्री की नियुक्ति करनी थी। वह नियुक्ति से पूर्व परीक्षा करना चाहता था। पांच-सात व्यक्ति आए। उसने सबको एक कमरे में बिठाकर कहा, आप सब यहां बैठें। मैं कमरे के बाहर ताला लगा देता हूं। जो भी ताले को खोलकर बाहर निकल आएगा, उसे मंत्री बनाऊंगा।

सबने सुना-सोचा- कितनी विचित्र परीक्षा। दरवाजा बंद। बाहर से ताला बंद और भीतर वालों से कहे कि बाहर आओ। यह असंभव है। छह व्यक्तियों ने सोचा, राजा पागल हो गया है। यह भी कोई परीक्षा होती है! दूसरे प्रकार से भी परीक्षा ली जा सकती थी। बाहर जाना कैसे संभव हो सकता है? वे हाथ पर हाथ रख बैठे रहे। कुछ पराक्रम नहीं किया। सातवां व्यक्ति अकर्मण्य नहीं था, पुरूषार्थी था। उसने सोचा, जरूर इस शर्त में कोई रहस्य है। राजा ऐसी शर्त क्यों रखता? मुझे अपना पुरूषार्थ करना है। वह उठा। दरवाजे के पास गया। उसे जोर से ढकेला, वह खुल गया। उसने बाहर आकर राजा का अभिवादन किया। दरवाजे पर कोई ताला लगाया ही नहीं था, केवल सबको भुलावे में रखा था।

राजा जानना चाहता था कि कौन कर्मण्य है और कौन अकर्मण्य। उन्होंने सोचा, जब बाहर ताला है तब दरवाजा कैसे खुलेगा? इसी भ्रम ने उन्हें अकर्मण्य बना डाला। वे बाजी हार गए। जिसने पुरूषार्थ किया, कर्मण्यता का परिचय दिया, वह जीत गया। वह मंत्री बन गया। साधना का क्षेत्र निर्विघ्न नहीं है। उसमें अनेक भुलावे हैं। उन भुलावों से साधक यदि अकर्मण्य बन साधना को भुला देता है तो साधना से भटक जाता है।

विचार मंथन

गृह मंत्रालय ने तय की थी 3 माह की समय सीमा

(लेखक- सनत जैन)

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तमिलनाडु सरकार की याचिका पर दिए गये फैसले के बाद एक महत्वपूर्ण संवैधानिक बहस शुरू हो गई है। यह बहस राष्ट्रपति या राज्यपालों द्वारा विधेयक की समय सीमा तक सीमित नहीं रह गई है। जिस तरह से राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से 14 बिंदुओं पर सलाह मांगी है। उसके बाद नई-नई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने जो आदेश दिया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय परिपत्र कई वर्ष पूर्व जारी कर चुका है। जिसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यपालों को निर्देश भेजे थे। तीन माह की समयावधि के अंदर विधेयक पर अंतिम फैसला लेने के लिए निर्देशित किया गया था। केंद्र सरकार के प्रशासनिक निर्देशों की समय सीमा का हवाला सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में यह सीमा तय की गई थी। इस गाइडलाइन के अनुसार, राष्ट्रपति और राज्यपालों को राज्यों से आने वाले विधेयकों पर अधिकतम तीन महीने के अन्दर निर्णय लेने थे। कई राज्यों के राज्यपाल यहां तक की राष्ट्रपति कार्यालय में लंबे समय से विधेयक लंबित पड़े थे। सहमति हो, असहमति हो या विधेयक को पुनर्विचार हेतु सरकार को लौटाना हो। यह व्यवस्था गृह मंत्रालय द्वारा सुनिश्चित की गई थी। ताकि राज्यों की विधानसभा से पारित विधेयकों को अनिश्चितकाल तक लंबित न रखा जा सके। यह प्रशासनिक सुधार और संघीय ढांचे के संतुलन बनाए रखने के लिए दिया गया था। विडंबना यह है, जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की बनाई इस गाइडलाइन का हवाला देते हुए राष्ट्रपति और राज्यपालों के निर्णयों पर समय सीमा तय करते हुए निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट इसके पहले भी कई बार राज्यपालों को निर्देश दे चुकी थी। जिसका पालन राज्यपालों द्वारा नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सरकार की असहजता झलकने लगी। दिल्ली, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र, केरल, पंजाब जहां-जहां विपक्षी दलों की सरकारें थी। वहां के राज्यपाल चुनी हुई सरकारों के विधानसभा से पारित विधेयकों को कई महीनो और वर्षों तक रोककर रखे हुए थे। ऑपरेशन लोटस और ईड़ी की कार्यवाही कर विपक्षी दलों को तोड़ने-फोड़ने का काम राज्यपालों के माध्यम से हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद केंद्र सरकार और भाजपा के लिए इस तरह का दबाव बनाना संभव नहीं होगा। जिसके कारण केन्द्र सरकार और भाजपा नेताओं में बड़ी बेचैनी देखने को मिल रही है। इस बेचैनी को इस रूप में समझा जा सकता है, केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रपति के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से सीधे सवाल पूछकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की यह एक दुर्लभ घटना है। यह स्थिति सरकार के दोहरे चरित्र को उजागर करती है। एक तरफ केंद्र स्वयं नियम बनाता है। दूसरी ओर उन्हीं नियमों से बचने की कोशिश करता है। राजनीतिक रूप से अपने फायदे के लिए केंद्र सरकार अपने ही बनाए नियमों का मन माफिक नतीजा निकल लेती है। केंद्र सरकार की यह प्रवृत्ति शासन की पारदर्शिता तथा संविधान के संघीय ढांचे पर प्रश्नचिह्न लगाती है। संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यों के अधिकारो का केंद्र सरकार दमन करती है। जिस विवाद को केंद्र सरकार ने जन्म दिया है। उसके बाद 8 राज्यों के विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। जिसके कारण बड़ा नुकसान संविधान को होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर केंद्र सरकार को आत्ममंथन करना चाहिए था। केन्द्र सरकार अपनी ही नीतियों का सम्मान क्यों नहीं करना चाहता है। यदि संवैधानिक संस्थाएं और संवैधानिक पद राजनीतिक और व्यक्तिगत हितों की पूर्ति के माध्यम बन जाएंगे, तो लोकतंत्र को किस तरह से सुरक्षित रखा जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार साफ संदेश दिया है संविधान सर्वोच्च है, कोई भी व्यक्ति या संस्था संविधान से बड़ी नहीं है। केंद्र को चाहिए कि वह संविधान और केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बनाए कानूनों और नियमों का ईमानदारी से पालन करे। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के लाभ हानि से जोड़कर, तोड़ने और मड़ोरने का प्रयास न करें। भारतीय संस्कृति में ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में तीनों शक्तियां अपने-अपने दायित्व को पूरा करती हैं। कर्म फल और प्रकृति के सिद्धांतों को ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी मानना पड़ता है। कोई भी एक दूसरे के क्षेत्र में जाकर अतिक्रमण नहीं करते हैं। कर्मफल के आधार पर ब्रम्हांड का संचालन होता है।

एमजी मोटर इंडिया ने बिक्री में बनाया एक नया रिकार्ड

नई दिल्ली।

अप्रैल महीने में एमजी मोटर इंडिया ने इस साल की अपनी सबसे बड़ी बिक्री दर्ज कर नया रिकॉर्ड कायम किया है। एमजी के पोर्टफोलियो में इलेक्ट्रिक कारों की संख्या आईसीई (इंटरनल कम्बिस्टन इंजन) वाहनों से कहीं अधिक है, और कंपनी की विंडसर ईवी देश की सबसे लोकप्रिय इलेक्ट्रिक कार बनी हुई है। कंपनी ने पिछले महीने कुल 5,829 कारें बेचीं, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रमुख हिस्सा रहा। हाल ही में एमजी ने विंडसर ईवी का प्रो वर्जन भी लॉन्च किया है, जो बड़ा बैटरी पैक और लंबी रेंज के साथ आता है। अप्रैल में भी विंडसर सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। इस साल के पहले चार महीनों में स्त्र मोटर की सेल्स में विंडसर ईवी की मांग खास रही। जनवरी में 3,277 यूनिट, फरवरी में 2,431, मार्च में 3,641 और अप्रैल में 3,660 विंडसर ईवी बिक चुकी हैं। इसके अलावा, हेक्टर एसयूवी की बिक्री भी लगातार बढ़ रही है जनवरी में 449, फरवरी में 515, मार्च में 547 और अप्रैल में 977 यूनिट्स बिकीं। झेडएस ईवी की मांग भी बढ़ी है, जनवरी में 265 यूनिट से लेकर अप्रैल में 864 यूनिट तक पहुंच गई है। एमजी की अन्य कारों में कॉमेट ईवी, एस्टर और ग्लॉस्टर की बिक्री में उतार-चढ़ाव दिखा। कुल मिलाकर, जनवरी में 4,455, फरवरी में 4,002, मार्च में 5,501 और अप्रैल में 5,829 गाड़ियां बिकीं। हाल ही में कॉमेट ईवी के बेस मॉडल एक्सीक्यूटिव की कीमत में 35,700 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

एल्युमीनियम मामूली तेजी के साथ 239 रुपये किलो

नई दिल्ली। हाजिर बाजार में सकारात्मक रुख के बीच सटोरियों के ताजा सौदे करने से सोमवार को वायदा बाजार में एल्युमीनियम की कीमतें 1.25 रुपये की मामूली तेजी के साथ 239.10 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गईं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून डिलीवरी वाले एल्युमीनियम अनुबंध की कीमत 1.25 रुपये अथवा 0.52 प्रतिशत की तेजी के साथ 239.10 रुपये प्रति किलोग्राम पर थी। इसमें 2,154 लॉट के लिए कारोबार हुआ। बाजार के विश्लेषकों ने कहा कि उपभोक्ता उद्योगों की मांग के बीच कारोबारियों के ताजा सौदे करने से वायदा बाजार में एल्युमीनियम कीमतों को समर्थन मिला।

रिलायंस पावर ने भूटान के साथ किया बिजली खरीद समझौता

नई दिल्ली। रिलायंस पावर ने ग्रीन डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड के साथ दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भूटान की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना में 50-50 प्रतिशत हिस्सेदारी वाला संयुक्त उद्यम खोला जाएगा7 इस परियोजना में 500 मेगावाट की क्षमता होगी और इसके लिए 2,000 करोड़ रुपये तक का पूंजीगत व्यय किया जाएगा। इस समझौते से भूटान के सौर ऊर्जा क्षेत्र में नए एफडीआई परियोजना के निवेश के रूप में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। कंपनी ने इसे क्षेत्रीय स्वच्छ ऊर्जा एकीकरण और भारत-भूटान सीमा पार ऊर्जा विनियमन में मददगार माना है।

मैजिकनाउ 2025-26 में खाद्य वितरण कारोबार में 20 प्रतिशत योगदान देगा

नई दिल्ली। स्थानीय स्तर पर ई-कॉमर्स सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी मैजिकपिन को उम्मीद है कि उसकी त्वरित वाणिज्य शाखा मैजिकनाउ चालू वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कुल खाद्य वितरण कारोबार में 20 प्रतिशत का योगदान देगी। मैजिकपिन के एक वे रिष्ठ अे धिकारी ने बताया कि मैजिकनाउ की शुरुआत सितंबर 2024 में हुई थी और कंपनी के कुल खाद्य वितरण कारोबार में उसकी 13 प्रतिशत हिस्सेदारी है। उन्होंने कहा` कि मैजिकनाउ 15 मिनट में सामान पहुंचाने वाली सेवा पहले ही हमारे कुल खाद्य वितरण कारोबार में 13 प्रतिशत का योगदान दे रही है। हम इसे चालू वित्त वर्ष के अंत तक 20 प्रतिशत तक बढ़ाने की राह पर हैं। मैजिकपिन ने मैजिकनाउ सेवाओं का विस्तार छह महानगरों से 20 घनी आबादी वाले शहरों तक किया है। उन्होंने कहा कि कंपनी को मैजिकनाउ के लिए उपभोक्ताओं और रेस्तरां भागीदारों से मजबूत प्रतिक्रिया मिली है।

भारत ने मालदीव के साथ 13 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए

10 करोड़ मालदीव रुपये के अनुदान से बढ़ेगी नौका सेवाएं

माले। भारत ने मालदीव के साथ 13 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौता ज्ञापनों में समुद्री संपर्क बढ़ाने, सामुदायिक आजीविका को मजबूत करने वाली परियोजनाएं शामिल हैं। इन ज्ञापनों में भारतीय अनुदान सहायता योजना- उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआईसीडीपी) के तहत लागू होने वाली 13 परियोजनाओं की कुल अनुदान राशि 10 करोड़ मालदीव रुपये है। मालदीव के विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि यह समझौता हर क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर है और दोनों देशों के बीच सहयोग को और भी मजबूत करेगा। मालदीव में भारतीय उच्चायोग ने इस समझौते को एचआईसीडीपी 3 के तहत मालदीव की नौका सेवाएं बढ़ाने के लिए एक कदम बताया। मालदीव सरकार के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील और भारत के उच्चायुक्त बालासुब्रमण्यम ने इन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता मालदीव और भारत के बीच समृद्धि और सशक्तिकरण के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम है। इससे नौका सेवाएं और समुद्री संपर्क मजबूत होंगे और साथ ही सामुदायिक आजीविका में भी सुधार आएगा।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बोर्ड में वारबर्ग की शाखा शामिल करने का प्रस्ताव खारिज

नई दिल्ली।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयरधारकों ने वैश्विक निजी इक्विटी फर्म वारबर्ग पिंकस की शाखा को बैंक के बोर्ड में शामिल करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। पिछले महीने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बोर्ड ने निवेशक वारबर्ग पिंकस एलएलसी की सहयोगी कंपनी करंट सी इन्वेस्टमेंट्स बीवी को लगभग 4,876 करोड़ रुपये के तरजीही इक्विटी शेयर जारी करने को मंजूरी दी थी। इसके तहत करंट सी इन्वेस्टमेंट्स को बैंक के बोर्ड में एक गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया था। बैंक ने इसके लिए डाक मतपत्र के जरिए शेयरधारकों की मंजूरी मांगी थी। शेयर बाजार को सोमवार को दी जानकारी के मुताबिक डाक मतपत्र की गिनती में पता चला कि केवल 64.10 प्रतिशत मत प्रस्ताव के पक्ष में थे, जबकि 35.90 प्रतिशत इसके खिलाफ थे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने कहा` कि विशेष प्रस्ताव अपेक्षित बहुमत नहीं होने के कारण पारित नहीं हुआ। कंपनी कानून के तहत, यदि प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 75 प्रतिशत वोट मिलते हैं, तो विशेष प्रस्ताव पारित हो जाता है।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बोर्ड में वारबर्ग की शाखा शामिल करने का प्रस्ताव खारिज

नई दिल्ली।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयरधारकों ने वैश्विक निजी इक्विटी फर्म वारबर्ग पिंकस की शाखा को बैंक के बोर्ड में शामिल करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। पिछले महीने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बोर्ड ने निवेशक वारबर्ग पिंकस एलएलसी की सहयोगी कंपनी करंट सी इन्वेस्टमेंट्स बीवी को लगभग 4,876 करोड़ रुपये के तरजीही इक्विटी शेयर जारी करने को मंजूरी दी थी। इसके तहत करंट सी इन्वेस्टमेंट्स को बैंक के बोर्ड में एक गैर-कार्यकारी निदेशक के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया था। बैंक ने इसके लिए डाक मतपत्र के जरिए शेयरधारकों की मंजूरी मांगी थी। शेयर बाजार को सोमवार को दी जानकारी के मुताबिक डाक मतपत्र की गिनती में पता चला कि केवल 64.10 प्रतिशत मत प्रस्ताव के पक्ष में थे, जबकि 35.90 प्रतिशत इसके खिलाफ थे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने कहा` कि विशेष प्रस्ताव अपेक्षित बहुमत नहीं होने के कारण पारित नहीं हुआ। कंपनी कानून के तहत, यदि प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 75 प्रतिशत वोट मिलते हैं, तो विशेष प्रस्ताव पारित हो जाता है।

शेयर बाजार गिरावट पर बंद

मुम्बई।

भारतीय शेयर बाजार सोमवार को गिरावट पर बंद हुआ। सप्ताह के पहले ही कारोबारी दिन बाजार में ये गिरावट दुनिया भर से मिले कमजोर संकेतों के साथ ही बिकवाली हावी रहने से आई है। आज दिग्गज कंपनियों रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईटी स्टॉक्स में बिकवाली से भी बाजार पर दबाव पड़ा। बैंकिंग शेयरों में बढ़त से हालांकि बाजार में गिरावट पर अंकुश लगा। दिन भर के कारोबार के बाद तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स अंत में सेंसेक्स 271.17 अंक करीब 0.33फीसदी की गिरावट लेकर 82,059.42 पर बंद हुआ। इसी प्रकार 50 शेयरों वाला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी कारोबार के अंत में 95 अंक तकरीबन 0.30 फीसदी नीचे आकर 24,944.85 पर बंद हुआ। इससे पहले शुक्रवार को भी बाजार गिरावट पर बंद हुआ था। आज कारोबार के दौरान निफ्टी रियल्टी और पीएसयू बैंक इंडेक्स सेक्टोरल इंडेक्सिस में सबसे अधिक तेजी रही। ये 2.25 फीसदी और 1.50 फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं अन्य सेक्टोरल इंडेक्सिस में बैंक निफ्टी, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल, फार्मा और हेल्थकेयर लाभ के साथ बंद हुए। वहीं आईटी, एफएमसीजी, मीडिया, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ऑयल एंड गैस में गिरावट रही। इसके अलावा निफ्टी आईटी इंडेक्स में सबसे ज्यादा 1.37 फिसदी की गिरावट रही। आज कारोबार के दौरान सेंसेक्स की कंपनियों में एटरनल (जोमैटो) में सबसे ज्यादा 3 फीसदी गिरावट दर्ज की गयी। इन्फोसिस में 1.95 फीसदी, टीसीएस में 1.20 फीसदी, टेक महिंद्रा में 1.19 फीसदी और एशियन पेंट्स पर 0.98 फीसदी की गिरावट आई। सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से केवल 9 शेयर गिरावट पर बंद हुए। पावर ग्रिड का शेयर सबसे ज्यादा 1.27 फीसदी बढ़कर बंद

हुआ। इसके अलावा बजाज फाइनेंस, एनटीपीसी, सीटेट बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी बैंक के शेयर भी उछले हैं। वहीं दुनिया भर के बाजारों की बात करें तो एशियाई बाजारों में सोमवार रही। निक्केई में 0.45 फीसदी की गिरावट जबकि ब्रोडर टॉपिक्स इंडेक्स नेगेटिव आउटलुक के साथ स्थिर रहा। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.47 फीसदी की गिरावट आई और एएसएक्स 200 में 0.37 फीसदी की गिरावट आई।वॉल स्ट्रीट पर शुक्रवार को बाजार मिले-जुले रहे। हालांकि एसएंडपी 500 ने लगातार पांचवीं बढ़त दर्ज की और साप्ताहिक प्रदर्शन मजबूत रहा। ब्रॉड-मार्केट इंडेक्स 0.70 फीसदी बढ़कर 5,958.38 पर बंद हुआ, जबकि नैस्डैक कंपोजिट 0.52 फीसदी बढ़कर 19,211.10 पर पहुंच गया। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 331.99 अंक या 0.78 फीसदी बढ़कर 42,654.74 पर पहुंच गया। इससे ब्लू-चिप इंडेक्स साल के लिए पॉजिटिव क्षेत्र में पहुंच गया। इससे पहले आज सुबह बाजार `गिरावट के साथ खुले।सेंसेक्स प्री-ओपन में मजबूती के बाद लाल निशान में खुला। सेंसेक्स 115 अंक की गिरावट लेकर 82,215 पर खुला। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 लगभग सपाट नोट पर 25 हजार के लेवल के ऊपर खुला।

1 जून 2025 से कोटक महिंद्रा बैंक के क्रेडिट कार्ड्स की मौज होगी खत्म

मुंबई।

1 जून 2025 से कोटक महिंद्रा बैंक अपने कई क्रेडिट कार्ड्स की शर्तों और रिवॉर्ड स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव करने जा रहा है, जिसका सीधा असर ग्राहकों की जेब पर होगा। खासकर रिवॉर्ड पॉइंट्स, शुल्क और ट्रांजैक्शन सीमाओं को लेकर किए गए बदलावों से कार्डधारकों को अब पहले से कम लाभ मिलेगा। प्रिवी लीग सिग्नेचर कार्ड रखने वालों को यूटिलिटी बिल, शिक्षा, इंश्योरेंस, वॉलेट लोड, सरकारी भुगतान और ऑनलाइन गेमिंग जैसी श्रेणियों में तय सीमा पार करने पर रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। साथ ही, फ्यूल और किराया भुगतान जैसे खर्चों पर किसी भी सीमा में रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। मोजो प्लेटिनम, जेन सिग्नेचर, कोटक 811 जैसे अन्य कार्ड्स पर भी रिवॉर्ड लिमिट कम की गई है। वहीं डिलाइट, फॉर्च्यून और 6ई रिवार्ड कार्ड्स पर उपरोक्त श्रेणियों में पूरी तरह से रिवॉर्ड बंद किए गए हैं। इसके साथ ही रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू भी घटा दी गई है।

बैंक ने ट्रांजैक्शन चार्ज में भी नया बोझ जोड़ा है। अब किराया और शिक्षा के किसी भी भुगतान पर 1 प्रतिशत शुल्क लगेगा। यूटिलिटी, फ्यूल, वॉलेट लोड और गेमिंग जैसे खर्चों पर भी तय लिमिट पार करने पर अतिरिक्त चार्ज वसूला जाएगा। उदाहरण के लिए प्रिवी लीग कार्ड पर 75,000 से अधिक के यूटिलिटी बिल या 50,000 से ज्यादा के फ्यूल खर्च पर 1 प्रतिशत शुल्क लगेगा। इसी तरह कोटक 811 कार्ड पर यूटिलिटी की सीमा 35,000 और फ्यूल की 25,000 तय की गई है। फ्यूल

सरचार्ज छूट की लिमिट को भी सीमित किया गया है। साथ ही कुछ कार्ड्स पर ब्याज दरें भी बढ़ा दी गई हैं, जो अब 3.75 प्रतिशत प्रतिमाह तक पहुंच चुकी हैं। स्थायी भुगतान निर्देश की विफलता पर अब न्यूनतम 450 और अधिकतम 5,000 तक का चार्ज लगेगा। यह बदलाव ग्राहकों के लिए काफी महंगा साबित हो सकता है।

भारत ने रिकॉर्ड 24 बिलियन डॉलर के स्मार्टफोन का निर्यात किया

भारत ने अकेले अमेरिका को 10.6 बिलियन डॉलर के स्मार्टफोन का निर्यात किया

नई दिल्ली। भारत ने वित्त वर्ष 2025 में स्मार्टफोन निर्यात में एक नई उपले ब्धि हा सिल की है। देश ने रिकॉर्ड 24.14 बिलियन डॉलर के स्मार्टफोन का निर्यात किया है, जो पिछले वर्ष के स्मार्टफोन निर्यात के 55 फीसदी ज्यादा है। भारतीय मेड इन इंडिया स्मार्टफोन की मांग अमेरिका, नीदरलैंड, इटली, जापान और चेक गणराज्य में बढ़ी है। भारत ने अकेले अमेरिका को 10.6 बिलियन डॉलर के स्मार्टफोन का निर्यात किया है। इस उछाल के साथ, भारतीय स्मार्टफोन निर्यात ने पेट्रोलियम उत्पादों और हीरे के निर्यात मूल्य को भी पार कर दिया है। भारत ने अपनी व्यवसायिक नुकसान से चीन के उत्पादन मार्ग को भी स्वीकार करते हुए, ऐप्पल जैसी दिग्गज कंपनियों को अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस को भारत में शिफ्ट करने का मौका दिया है। यह नया उत्कृष्टा का पहलू दिखाता है जो भारत को एक मान्यता प्राप्त निर्यात नेतृत्व प्राप्त कराने के लिए तैयार कर रहा है। मेड इन इंडिया स्मार्टफोन अब दुनिया भर में अपनी नई प्रतिष्ठा बना रहे हैं। वित्त वर्ष 2025 में भारतीय स्मार्टफोन्स का निर्यात भारी समृद्धि प्राप्त कर रहा है, जो स्मार्टफोन उत्पादन में सारे देशों के बीच स्थान बदल देगा।

एप्पल के आईओएस 19 में उन्नत बैटरी ऑप्टिमाइजेशन फीचर आएगा

नई दिल्ली।

स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल अपने नए ऑपरेटिंग सिस्टम आईओएस 19 में एक उन्नत और स्मार्ट बैटरी ऑप्टिमाइजेशन तकनीक पेश करने जा रही है। यह स्मार्ट बैटरी आईफोन यूजर्स के लिए बैटरी प्रबंधन को काफी बेहतर बनाएगी। यह फीचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पर आधारित होगा और यूजर की फोन उपयोग की आदतों को समझकर पावर की खपत को अधिक कुशलता से नियंत्रित करेगा। इसके साथ ही यह फोन की बैटरी कितनी जल्दी फुल चार्ज होगी, इसका भी अनुमान यूजर को देगा। पहले यह माना जा रहा था कि यह एआई आधारित फीचर केवल आने वालेआईफोन 17 मॉडल तक सीमित रहेगा, लेकिन अब यह जानकारी मिली है कि आईओएस 19 अपडेट के माध्यम से यह सभी समर्थित आईफोन में उपलब्ध होगा।आईफोन17 की खासियत यह भी बताई जा रही है कि यह अब तक का सबसे पतला आईफोन होगा और इसकी बैटरी साइज भी कम हो सकती है, इसलिए बेहतर बैटरी मैनेजमेंट फीचर की जरूरत और बढ़ जाती है।

यह नया फीचर यूजर के ऐप उपयोग के पैटर्न को ट्रैक करेगा और यह बताएगा कि कौन-से ऐप सबसे ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा, लॉक स्क्रीन पर फोन के पूरे तरह चार्ज होने में लगने वाले समय की जानकारी भी दिखेगी। रिपोर्ट के अनुसार, एप्पल जून में अपने वार्षिक डब्ल्यूडब्ल्यूडीसी इवेंट में आईओएस 19 लॉन्च कर सकता है, जबकि आम यूजर्स को यह अपडेट सितंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। आईओएस 19 के साथ कई अन्य नए टूल्स और फीचर्स भी आएंगे, जो आईफोन उपयोगकर्ता के अनुभव को और बेहतर बनाएंगे।

मारुति सुजुकी डिजायर अब मिलेगी साउथ अफ्रीका में

नई दिल्ली।

मारुति सुजुकी डिजायर अब साउथ अफ्रीका के बाजार में भी उपलब्ध हो गई है। खास बात यह है कि साउथ अफ्रीका में यह कार ऑटोमैटिक सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ आती है, जो भारत में उपलब्ध नहीं है।

भारत में डिजायर को 5-स्पीड एएमटी ऑटोमैटिक विकल्प के साथ पेश किया जाता है, जबकि वहां इसे 5-स्पीड मैनुअल और सीवीटी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स में मिलती है।

डिजाइन की बात करें तो दोनों संस्करणों में कोई बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन साउथ अफ्रीका में मिलने वाले मॉडल में एलईडी हेडलाइट्स नहीं हैं। वहीं, ड्यूल-टोन 15-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो भारतीय मॉडल के साधारण सिल्वर अलॉय से बेहतर नजर आते हैं। इंटीरियर में भी ज्यादातर समानता है, लेकिन डैशबोर्ड के बीच में सिल्वर स्ट्रिप नहीं है। इसके अलावा, इस मॉडल में 7-इंच का बेसिक इंफोटेनमेंट सिस्टम, 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस फोन चार्जर, पुश स्टार्ट बटन जैसे फीचर्स मौजूद हैं, लेकिन सिंगल पैनल इलेक्ट्रिक सनरूफ जैसे कुछ खास फीचर्स नहीं हैं।

साउथ अफ्रीका में इस कार को 1.2-लीटर 3-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च किया गया है, जो 81 बीएचपी और 112 एनएम टॉर्क उत्पन्न करता है।

कुल मिलाकर, डिजायर का यह नया संस्करण ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बनाने को तैयार है। सुरक्षा के लिहाज से डिजायर में 6 एयरबैग्स, रियर पार्किंग सेंसर्स, रियर व्यू कैमरा, एबीएस के साथ ईबीडी और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स शामिल है।

एसयूवी बोलेरो और बोलेरो नियो का नया बोल्ड एडिशन पेश

नई दिल्ली।

स्वदेशी कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एसयूवी बोलेरो और बोलेरो नियो का नया बोल्ड एडिशन पेश किया है। कंपनी ने आधिकारिक सोशल मीडिया पर दोनों मॉडलों के वीडियो भी जारी किए हैं, जिनमें बोलेरो को डायमंड व्हाइट रंग में दिखाया गया है, जिसके साइड और डोर पैनल पर तीन ग्राफिक्स हैं। लंबे समय से अपडेट न होने के बाद यह नए डिजाइन और स्टाइल एलिमेंट के साथ बाजार में उतारा गया है, जिससे दोनों गाड़ियों की रोड प्रजेंस बेहतर हुई है। फ्रंट ग्रिल ऑल-ब्लैक है जिसमें गन मेटल फिनिश के साथ वर्टिकल स्लैट हैं और महिंद्रा का क्रोम फिनिश वाला लोगो भी है। फ्रंट बंपर में मेटल फिनिश और पीले ग्राफिक्स के साथ ब्लैक पैनल में फॉग लैंप दिए गए हैं। बोलेरो के साइड बॉडी पैनल और डी-पिलर के आगे बोल्ड एडिशन बैज नजर आता है। रियर लैंप क्लियर लेंस वाले ट्विक्ड हैं। इंटीरियर में ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है, ब्लूटूथ साउंड सिस्टम बना हुआ है। डिजिटल इंफॉर्मेशन क्लस्टर ड्राइवर को माइलेज, ट्रिप डिस्टेंस और ओपन डोर वॉर्निंग जैसी जानकारियां देता है। बोलेरो में 1493 सीसी डीजल इंजन है, जो 3600 आरपीएम पर 75 बीएचपी पावर और 1600-2200 आरपीएम पर 210 एनएम टॉर्क जनरेट करता है, जो 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जुड़ा है। वहीं, बोलेरो नियो बोल्ड एडिशन में सिल्वर फिनिश मेश के साथ क्रोम-फिनिश फ्रंट ग्रिल, हनीकॉम्ब डिजाइन वाला फ्रंट बंपर और काले रंग के स्पेयर व्हील कवर व रियर एयर कंडीशनिंग वेंट शामिल हैं। इसमें 1.5-लीटर एमहॉक डीजल इंजन है, जो 3750 आरपीएम पर 98.5 बीएचपी और 1750-2250 आरपीएम पर 260 एनएम टॉर्क देता है। यह दोनों मॉडल महिंद्रा की एसयूवी रेंज को और मजबूत करेंगे।इसके केबिन में डार्क थीम, ऑल-ब्लैक अपहोल्स्ट्री, नेक पिलो और सीटबेल्ट कवर दिए गए हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक बढ़ा सकता है रिस्क बफर का दायरा

वित्त वर्ष 25 में सरकार को रिकॉर्ड सरप्लस ट्रांसफर की उम्मीद

नई दिल्ली।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के केंद्रीय बोर्ड ने पिछले सप्ताह अपनी बैठक में आर्थिक पूंजी ढांचे (ईसीएफ) की समीक्षा के दौरान आकस्मिक जोखिम बफर (सीआरबी) का दायरा बढ़ाने के लिए सरकार से मंजूरी मांगी है। इस मामले से संबंधित जानकारी सूत्रों के मुताबिक` मिली है। बिमल जालान समिति की सिफारिश के अनुसार मौजूदा बफर केंद्रीय बैंक के बहीखाते का 5.5 से 6.5 फीसदी है। रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को हस्तांतरित किया जाने वाला अधिशेष इस बात पर निर्भर करता है कि केंद्रीय बैंक कितना जोखिम बफर बनाए रखना चाहता है। जोखिम बफर अधिक होने का मतलब साफ है कि सरकार को हस्तांतरित की जाने वाली अधिशेष रकम कम होगी। इसी प्रकार जोखिम बफर कम रहने पर सरकार के लिए अधिशेष रकम अधिक होगी। एक सूत्र ने कहा` कि जालान समिति द्वारा सुझाए गए ढांचे ने पिछले पांच साल के दौरान काफी हद तक अच्छा काम किया है। इसका दायरा काफी महत्वपूर्ण है। मौजूदा चुनौतियों और उतार-चढ़ाव के मद्देनजर हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़े दायरे के बारे में कैसे सोचा जा सकता है।' अगली बैठक 23 मई को होगी। उसमें खातों को अंतिम रूप दिया जाएगा और केंद्र की मंजूरी के बाद नई सीमा के आधार पर

हस्तांतरण योग्य अधिशेष पर निर्णय लिया जाएगा।

बिहार में 4 हजार करोड़ की ठगी का खुलासा, तेलंगाना पुलिस की कार्रवाई, दो महिला-पुरुष गिरफ्तार

पटना (एजेंसी)। बिहार के पटना में 4 हजार करोड़ रुपए के ठगी का मामला सामने आया है। बिहार और तेलंगाना पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने दानापुर से दो महिला-पुरुष को गिरफ्तार किया है जिसे तेलंगाना पुलिस अपने साथ हैदराबाद ले गयी। दानापुर पुलिस के थानाध्यक्ष पी.के.भारद्वाज ने बताया कि हैदराबाद में स्थित एक कंपनी में दानापुर से चार हजार करोड़ रुपए की ठगी की गयी थी। इस मामले में तेलंगाना पुलिस ने दानापुर पुलिस के सहयोग से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक सुषमा राज और रविंद्र कुमार सिंह के पास से 8 लाख तीस हजार 910 रुपया नगद, 6 पासपोर्ट, 10 मोबाइल फोन, बैंक के स्क्रीम क्रेडिट कार्ड, तीन पासबुक, 16 आई कार्ड, 8 घड़ी व 11 पीस सोने व डायमंड के जेवरात बरामद किए गए हैं। अब तक का इतना बड़ा ठगी का मामले का खुलासा होने से पुलिस भी हैरान है। बताया जाता है कि दोनों आरोपी हैदराबाद में एक कंपनी के नाप पर निवेशकों से ठगी की थी। इस मामले में हैदराबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पटना से दोनों आरोपी को गिरफ्तार किया।

आईएसआई से जुड़े 2 आतंकी गिरफ्तार

हैदराबाद (एजेंसी)। हैदराबाद में आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े दो संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। इन पर बम धमाके की साजिश रचने का आरोप है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पुलिस ने दोनों को पकड़ा और बम ब्लास्ट होने से बचा लिया। संदिग्ध आतंकियों की पहचान सिराज उर रहमान (29) और सैयद समीर (28) के रूप में हुई है। पुलिस को संदेह है कि इन दोनों को सऊदी अरब में एक्टिव ब्लूक्रूस् मॉड्यूल से निर्देश मिल रहे थे, जो हैदराबाद में हमला करवाना चाहता था। पुलिस को इनके पास से अमोनिया, सल्फर और एल्युमिनियम पाउडर जैसे विस्फोटक सामान मिले हैं। सिराज ने विस्फोटक सामग्री विजयनगरम से जुटाई थी। फिलहाल संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ जारी है। जल्द ही कोर्ट में इनकड़ी पेशी होगी।

हरियाणा में 3 महीने में 4100 लोग लापता

चंडीगढ़ (एजेंसी)। हरियाणा में तीन महीने में 4100 से अधिक लोगों के मिसिंग होने के मामले सामने आए हैं। इन मामलों पर नाराजगी जाहिर करते हुए हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने स्वत- संज्ञान लिया है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि वर्ष 2025 की पहली तिमाही में 4100 से अधिक लोग लापता हुए, यानी प्रतिदिन औसतन 45 से अधिक व्यक्ति गायब हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त 1000 से अधिक किडनैपिंग के मामले दर्ज हुए हैं। साथ ही मर्डर और गैर इरादतन हत्या की घटनाओं में भी पिछले वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। ये आंकड़े सार्वजनिक सुरक्षा तंत्र के विफल होने की गंभीर स्थिति को दर्शाते हैं।

रेलवे टिकट पर पीएम मोदी की फोटों, आगबबूला हो गई आप

नई दिल्ली (एजेंसी)। आम आदमी पार्टी ने रेलवे टिकट पर आपत्ति जाहिर की है। पार्टी टिकट पर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पीएम मोदी की फोटो देखकर आगबबूला हो गई। आप ने प्रचार का जरिया बताया है। आम आदमी पार्टी ने पोस्ट में लिखा कि सेना और ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर अपना प्रचार कर रहे महामानव। आप ने इस लाइन के द्वारा सीधा निशाना पीएम मोदी साधा है। इसके बाद आपने लिखा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तानी आतंकवादियों को कड़ा सबक सिखाया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें भी अपने प्रचार और छपास का मौका ढूंढ लिया है। अब रेलवे टिकट पर मोदी को फोटो के साथ छापा जा रहा है। अगर फोटो लगानी ही हैं, सेनाओं के प्रमुखों या कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की लगाए। आप ने पोस्ट के साथ रेलवे टिकट की फोटो भी साझा की है। यह किसी यात्री ने भोपाल से झांसी तक के लिए बुक की है। टिकट में नीचे की तरफ पीएम मोदी की सैल्यूट करती तस्वीर भी है, जिसके बगल में लिखा है,ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है,एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है।

नीतीश से मिलकर चिराग पासवान का बयान, फिलहाल सीएम पद के लिए कोई रिक्ति नहीं

पटना (एजेंसी)। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान ने सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है।कभी नीतीश के खिलाफ बिगुल फूंकने वाले चिराग अब उनकी तारीफ कर रहे हैं। नीतीश से मुलाकात के बाद चिराग ने कहा कि बिहार में फिलहाल सीएम पद के लिए कोई रिक्ति नहीं है। चुनाव नतीजों के बाद पीएम मोदी के नेतृत्व और विजन के तहत सीएम नीतीश कुमार एक मजबूत एनडीए सरकार का नेतृत्व करने वाले है। वहीं, तमाम अटकलों के बीच चिराग लगातार दावा कर रहे हैं कि वे नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। दिवंगत दलित नेता रामविलास पासवान के बेटे ने कहा कि मेरे प्रधानमंत्री मेरे दिल में रहते हैं... अगर जरूरत पड़ी तब मैं दुनिया को फाड़कर दिखा दूंगा। इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं, इसके बाद पासवान जूनियर अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के लिए अच्छी सीटें हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को खुश करने की कोशिश में हैं। उनका मोदी का हनुमान वाला दावा पिछले बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी सुर्खियों में रहा था, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ नहीं बल्कि अलग से चुनाव लड़ा था। अक्टूबर-नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की संभावनाओं को मजबूत करने के लिए चिराग सभी दलित समुदायों तक पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। राज्य की आबादी में दलितों की हिस्सेदारी 16.04 प्रतिशत है और वे राज्य में किसी भी चुनाव के नतीजे तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। दूसरी ओर, बिहार में यादव के बाद पासवान दूसरी सबसे बड़ी जाति है, जो राज्य की आबादी का 5.311 प्रतिशत है।

विदेश जाने वाली टीम के लिए कांग्रेस से नाम नहीं मांगे: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने कांग्रेस के उन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें दावा किया गया था कि सरकार ने विपक्षी पार्टी से विदेशी दौरों के लिए चार सांसदों के नाम मांगे और फिर उनमें से तीन को खारिज कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को इस मिशन की जानकारी सिर्फ शिष्टाचारवश दी गई थी, न कि औपचारिक प्रक्रिया के तहत।एक अंग्रेजी अखबार से बातचीत में रिजिजू ने कहा, कभी भी यह प्रथा नहीं रही है कि विपक्षी पार्टियों से उनके नाम मांगे जाएं। हमने उन्हें केवल शिष्टाचार के तहत सूचित किया।

कांग्रेस द्वारा अपने सुझावों की उपेक्षा को लेकर जताई गई नाराजगी पर जवाब देते हुए रिजिजू ने कहा कि सरकार ने उन्हीं लोगों को चुना जो मिशन के लिए सबसे उपयुक्त थे। उन्होंने कहा, हमें हैरानी हो रही है कि कांग्रेस शशि थरूर और मनीष तिवारी जैसे नेताओं के नामों पर सवाल उठा रही है। दोनों विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विपक्ष की तरफ से प्रभावी आवाज रहे हैं और अभी एक साल भी नहीं हुआ जब कांग्रेस ने खुद थरूर को विदेशी मामलों की स्थायी समिति का अध्यक्ष बनाया था। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि थरूर और तिवारी को इसलिए चुना गया ताकि पार्टी नेतृत्व को नीचा दिखाया जा सके। इस पर रिजिजू ने कहा, यह केवल एक झूठा संकेत है। हमने किसी पार्टी की आंतरिक राजनीति, असुरक्षा या ईर्ष्या के आधार पर नहीं, बल्कि योग्यता के आधार पर चयन किया है। हमने सलमान खुर्शीद और अमर सिंह (पंजाब के कांग्रेस सांसद) को भी चुना है, अब इस पर क्या कहेंगे? कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस चयन प्रक्रिया की आलोचना करते हुए कहा था, यह मोदी सरकार की पूर्ण असंवेदनशीलता और उसकी वह सस्ती राजनीति दर्शाता है जो वह हमेशा राष्ट्रीय मुद्दों पर खेलती है।कांग्रेस का मानना है कि थरूर को इसलिए चुना गया क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर पार्टी लाइन से हटकर बयान दिया था। जब कांग्रेस इस मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की भूमिका को निशाने पर ले रही थी, तब थरूर ने कहा था कि वे इस ऑपरेशन पर एक गर्वित भारतीय के तौर पर बोल रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने अपने प्रस्तावित नामों की सूची से थरूर को हटा दिया था। राहुल की सूची में गौरव गोगोई, आनंद शर्मा, राजा वड़िंग और सैयद नसीर हुसैन शामिल थे, जिनमें से केवल आनंद शर्मा के नाम को ही स्वीकार किया गया।बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने का भारत का संदेश लेकर सात सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश जाएंगे, जिनमें से चार प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व सत्तारूढ़ दलों के नेता जबकि तीन की अगुवाई विपक्षी दलों के नेता करेंगे। कांग्रेस के चार सांसद इन टीमों का हिस्सा हैं और केरल के सांसद शशि थरूर एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।

श्रीलंकाई तमिल नागरिक ने जान का खतरा बताकर पनाह मांगी, सुप्रीम कोर्ट बोला- भारत धर्मशाला नहीं, जो हर किसी को शरण दे

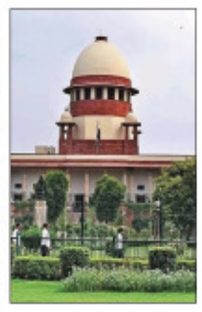

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शरणार्थी से जुड़े एक मामले में सोमवार को कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। दुनियाभर से आए शरणार्थियों को भारत में शरण क्यों दें? हम 140 करोड़ लोगों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। हम हर जगह से आए शरणार्थियों को शरण नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी श्रीलंका के एक नागरिक की याचिका खारिज करते हुए की। दरअसल, मद्रास हाईकोर्ट ने श्रीलंकाई नागरिक को यूएपीए मामले में 7 साल की सजा पूरी होते ही तुरंत भारत छोड़ देने का आदेश दिया। इसके खिलाफ उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हस्तक्षेप करने की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह वीजा लेकर भारत आया है। श्रीलंका में उसकी जान को खतरा है। उसकी पत्नी और बच्चे भारत में बसे हैं, और वह तीन साल से हिरासत में है, लेकिन निर्वासन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। यह केस एक श्रीलंकाई तमिल नागरिक का है, जिसे 2015 में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम से जुड़े होने के शक में गिरफ्तार किया गया था। एलटीटीई श्रीलंका में पहले सक्रिय एक आतंकी संगठन था। 2018 में एक निचली अदालत ने उसे गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत 10 साल की सजा सुनाई। 2022 में मद्रास हाई कोर्ट ने सजा को सात साल कर दिया और कहा कि सजा पूरी होने के बाद उसे देश छोड़ना होगा और निर्वासन से पहले शरणार्थी शिविर में रहना होगा।

सभी दलों के प्रतिनिधियों को दुनिया भर में भेजने की नौबत क्यों आई? आदित्य ठाकरे ने पहलगाम अटैक को लेकर सरकार से पूछे सवाल

मुंबई (एजेंसी)। शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि हमारी भूमिका पहले दिन से ही स्पष्ट है... पहले दिन से विपक्ष के सारे दलों ने एक सुर में कहा था कि हम प्रधानमंत्री के साथ हैं क्योंकि हमें पाकिस्तान को दिखाना है कि हमारी ताकत क्या है और आतंक के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे और एक साथ रहेंगे लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने(भाजपा) राजनीति शुरू की है... राजनीति ना करते हुए सभी दलों को साथ रखना चाहिए। विदेश मंत्री को बताना चाहिए कि क्यों ऐसी नौबत आई कि आज सभी दलों के प्रतिनिधियों को दुनिया भर में भेजना पड़ रहा है? कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा है कि पहलगाम में आतंकवादी आए कैसे?

केंद्र ने रविवार को सात प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों के नामों की घोषणा की, जिनमें विभिन्न दलों के राजनीतिक नेता, सांसद और पूर्व मंत्री शामिल होंगे, जो 'ऑपरेशन सिंदूर' की पृष्ठभूमि में आतंकवाद से निपटने के भारत के संकल्प को सामने रखने के लिए विश्व की राजधानियों की यात्रा करेंगे। प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व बैजयंत पांडा, रविशंकर प्रसाद (दोनों भाजपा), संजय कुमार झा (जदयू), श्रीकांत शिंदे (शिवसेना), शशि थरूर (कांग्रेस), कनिमोई (द्रमुक) और सुप्रिया सुले (राकांपा-एसपी) कर रहे हैं। वे कुल 32 देशों तथा बेल्जियम के ब्रसेल्स में स्थित यूरोपीय संघ के मुख्यालय का दौरा करेंगे।

जयशंकर पर राहुल गांधी का निशाना, उनकी चुप्पी सिर्फ बयानबाजी नहीं है, यह निंदनीय

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर पर उनकी टिप्पणी के लिए फिर से निशाना साधा है। जिसमें जयशंकर ने कहा था कि भारत ने पाकिस्तान को अपनी धरती पर आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाने के बारे में सूचित कर दिया है।

सोशल मीडिया पोस्ट में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जयशंकर की चुप्पी को निंदनीय बताया। राहुल गांधी ने लिखा, विदेश मंत्री जयशंकर की चुप्पी सिर्फ बयानबाजी नहीं है, यह निंदनीय है। इसलिए, मैं फिर से पूछूंगा कि भारत ने कितने विमान खो दिए, क्योंकि पाकिस्तान को पता था? यह कोई चूक नहीं थी। यह एक अपराध था और देश को सच्चाई जानने का हक है।'

उन्होंने पोस्ट में लिखा था, 'हमारे हमले की शुरुआत में पाकिस्तान को सूचित करना एक अपराध था। विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि भारत सरकार ने ऐसा किया। इन्हें किसने अधिकृत अथोरिटाइज्ड किया? इसके परिणामस्वरूप हमारी वायुसेना ने कितने विमान खो दिए?'

राहुल गांधी द्वारा की गई पोस्ट के तुरंत बाद विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया देकर इन तथ्यों को गलत तरीके से पेश करना बताया। विदेश मंत्रालय ने कहा, 'विदेश मंत्री ने कहा था कि हमने पाकिस्तान को शुरुआत में ही चेतावनी दे दी थी जो कि स्पष्ट रूप से ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने के बाद का चरण है। इस गलत तरीके से शुरू होने से पहले की घटना बताया जा रहा है। तथ्यों की इस पूरी तरह से गलत प्रस्तुति की निंदा है।'

दरअसल जयशंकर ने कहा था, 'ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में, सरकार ने पाकिस्तान को संदेश भेजा था कि हम आतंकवादियों के बुनियादी ढांचे पर हमला कर रहे हैं। हम सेना पर हमला नहीं कर रहे हैं। इसलिए, सेना के पास इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप न करने और अलग रहने का विकल्प है। उन्होंने उस अच्छी सलाह को न मानने का फैसला किया।'

ऑपरेशन सिंदूर वाली टीम से दूरी बना रहीं ममता बनर्जी, युसुफ पठान की लगा दी क्लास

कोलकाता (एजेंसी)। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ऑपरेशन सिंदूर से दूरी बना रहीं हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने पाकिस्तान की पोल खोलने और ऑपरेशन सिंदूर का सच बताने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को विदेश दौरे पर भेजने का फैसला किया है। इस टीम के लीडर्स के नाम का भी ऐलान कर दिया गया है। सरकर ने टीएमसी सांसद और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान का नाम इस लिस्ट में शामिल किया था। हालांकि सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने युसुफ पठान को इस दौरे का हिस्सा बनने से मना कर दिया है।

इस कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए तृणमूल कांग्रेस नेता ने कहा, हमारा मानना है कि राष्ट्र सबसे ऊपर है, और हमने अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई करने की जरूरत है उसके लिए केंद्र सरकार को अपना समर्थन देने का वचन दिया है। हमारे सशस्त्र बलों ने देश को गौरवान्वित किया है और हम हमेशा उनके कर्जदार रहेंगे। सीएम ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि वह केंद्र सरकार के इस अभियान का हिस्सा नहीं बन रही है। टीएमसी ने आधिकारिक रूप से इसकी कोई वजह नहीं बताई है। पार्टी ने केंद्र सरकार को इसकी जानकारी दे दी है। केंद्र सरकार ने ऐलान किया था कि 7 सर्वदलीय टीमों को अलग-अलग देशों के दौरे पर भेजा जाएगा। वे ऑपरेशन सिंदूर का सच बताएंगे। इसके आलावा आतंकवाद और पाकिस्तान प्रायोजित दहशतगर्दी की पोल खोलेंगे। मोदी सरकार की विदेश जाने वाली सर्वदलीय टीम में बीजेपी के रविशंकर प्रसाद और बैजयंत पांडा, कांग्रेस के शशि थरूर, जेडीयू के संजय कुमार,डीएमके की कनिमोझी, एनसीपी-एसपी की सुप्रिया सुले और शिवसेना के श्रीकांत शिंदे का नाम है। ये सभी अलग-अलग प्रतिनिधिमंडलों की अगुआई करेंगे। कुल 51 राजनेताओं को विदे भेजा जा रहा है। ये प्रतिनिधिमंडल 32 देशों के साथ ब्रुसेल्स में यूरोपीय यूनियन के हेडक्वार्टर का भी दौरा करेंगे।इस प्रतिनिधिमंडल में पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद, एमजे अकबर, आनंद शर्मा, वी मुरलीधरन, सलमान खुर्शीद, एसएस अहलूवालिया को भी शामिल किया गया है। ये सभी वर्तमान में संसद के सदस्य नहीं हैं। तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने रविवार को कहा कि विदेश नीति केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है और उसे ऐसे मामलों की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

फिर मुंबई में कोरोना ने दी दस्तक ? दो संदिग्ध मरीजों की मौत से चिंता बढ़ी

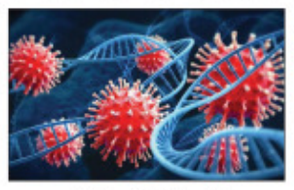

मुंबई (एजेंसी)। एशियाई देशों में कोरोना के फैलने की खबर ने एक बार फिर हड़कंप मचा दिया है और अब स्वास्थ्य व्यवस्थाओं ने भी एहतियात बरतना शुरू कर दिया है। इस बीच कोरोना संक्रमण ने मुंबई में भी दस्तक दे दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुंबई के केईएम अस्पताल में दो संदिग्ध कोरोना मरीजों की मौत होने की खबर से चिंता बढ़ने लगी है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि मुंबई में कोरोना संक्रमण का प्रवेश हुआ है? लेकिन आशंकाएं बढ़ रही हैं क्योंकि दोनों मरीजों की मौत से पहले किए गए परीक्षणों से पता चला है कि वे कोरोना वायरस से संक्रमित थे। उधर केईएम अस्पताल ने स्पष्ट किया है कि संदिग्ध कोरोना वायरस रोगियों की मौत उनकी अंतर्निहित चिकित्सा स्थितियों के कारण हुई है। इस बीच दो मरीजों की मौत के बाद प्रशासन भी सतर्क हो गया है। चूँकि दोनों मृतक मरीजों में कोरोना के लक्षण दिख रहे थे, इसलिए उन्हें केईएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। केईएम अस्पताल के सूत्रों के अनुसार, दोनों मरीजों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनमें बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई के लक्षण थे। उनके नमूने परीक्षण के लिए भेजे गए हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट अभी तक उपलब्ध नहीं है। दोनों संदिग्ध कोरोना मरीजों को आईसीयू में रखा गया था। उन्हें उचित उपचार मिल रहा था। लेकिन उनकी हालत बिगड़ने के कारण उन्हें बचाना संभव नहीं हो पाया। हालाँकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मृतकों में 58 वर्षीय महिला की मौत कैंसर से और 13 वर्षीय लड़की की मौत किडनी की बीमारी से हुई है। वहीं मुंबई महानगरपालिका ने इस घटना को गंभीरता से लिया है। मरीजों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने का काम शुरू हो गया है। इसके अलावा, नागरिकों से मास्क का उपयोग करने, सामाजिक दूरी बनाए रखने और हाथ धोने जैसे कदम उठाने का आग्रह किया गया है। प्रशासन ने नागरिकों को बिना घबराये सावधानी बरतने की सलाह दी है।

* पूर्व महापौर के बयान से भ्रम की स्थिति

उधर मुंबई की पूर्व महापौर किशोरी पेडनेकर के इस बयान से कि दोनों मरीजों की मौत कोरोना वायरस से हुई है, भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है और केईएम अस्पताल में दोनों मरीजों की मौत के वास्तविक कारण को लेकर भय का माहौल पैदा हो गया है।

* एशियाई देशों में बढ़ा कोरोना का आतंक

एशियाई देशों में कोरोना का खौफ अचानक बढ़ गया है। हांगकांग और सिंगापुर में कोरोना के नए स्ट्रेन के कारण मरीजों की संख्या बढ़ रही है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, मई के पहले सप्ताह में सिंगापुर में कोरोना मरीजों की संख्या में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

अगर बलूचिस्तान हुआ आजाद तो भारतीय हिंदू कर सकेंगे हिंगलाज माता के दर्शन

-यह मंदिर हिंदू धर्म के 51 शक्तिपीठों में से एक, मुस्लिम भी रखते हैं आस्था

नई दिल्ली (एजेंसी)। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर और पीएम शाहबाज शरीफ की गलत नीतियों का खामियाजा आज पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर ऐसा जख्म दिया है, जिसे वह दशकों तक नहीं भूला पाएगा। वहीं, बलूचिस्तान प्रांत के लोग भी अब अत्याचार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। बलूच विद्रोहियों ने हाल ही में ऐसी घटनाओं और अटैक को अंजाम दिया है, जिससे पूरा पाकिस्तान थर्रा गया है। बचूल लोगों ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग बताते हुए खुद को अलग देश घोषित कर दिया है। वहां के नेताओं का कहना है कि वे अब पाकिस्तान के साथ नहीं रह सकते हैं और बलूचिस्तान अब स्वतंत्र राष्ट्र है। इसके साथ ही बलूचों ने भारत और संयुक्त राष्ट्र से कहा कि बलूचिस्तान को एक अलग देश का दर्जा दिया जाए। यदि ऐसा होता है तो भारत लाखों करोड़ों हिन्दुओं का सपना साकार हो जाएगा।

बलूचों द्वारा आए दिन पाक सरकार को चेतावनी दी जा रही है, उससे साफ है कि अलग राष्ट्र की मांग ने जोर पकड़ लिया और वह इसे लेकर ही रहेंगे। अगर बलूचिस्तान एक स्वतंत्र देश बन जाता है, तो देश के हिंदुओं के लिए दो बड़े और ऐतिहासिक मंदिरों के द्वार खुल जाएंगे। हिंगलाज माता मंदिर और कटासराज मंदिर। जिस तरह से भारतीय सिख समुदाय के लिए करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया और गुरुद्वारा दरबार साहिब तक पहुंच आसान हुई, ठीक उसी तरह से हिंगलाज माता और कटासराज मंदिर के द्वार भारतीय हिंदू के लिए खुल सकते हैं।

यह मंदिर भारत के हिंदुओं के लिए खास है, जहां बहुत कम भारतीय पहुंचते हैं। हिंगलाज माता मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के लासबेला जिले में स्थित है। यह मंदिर हिंदू धर्म के 51 शक्तिपीठों में से एक है और इसे हिंगलाज शक्तिपीठ भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान शिव माता सती के शव को लेकर विचरण कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने सती के शरीर के टुकड़े किए और जहां-जहां ये गिरे वहां शक्तिपीठ बने। हिंगलाज वह स्थान है जहां माता सती का मस्तक गिरा था। यह मंदिर हिंगोल नदी के किनारे स्थित है और चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा है। यहां की देवी को 'हिंगलाज देवी' या 'नानी मां' के नाम से जाना जाता है, खासकर सिंधी और बलूच हिंदू समुदायों में इसका विशेष महत्व है।

इस स्थान की विशेषता यह भी है कि यहां मुस्लिम समुदाय के लोग भी आस्था रखते हैं और देवी को 'नानी पीर' के रूप में मानते हैं। हिंगलाज यात्रा एक कठिन, लेकिन आध्यात्मिक रूप से अहम मानी जाती है। इसे 'हिंगलाज तीर्थयात्रा' भी कहा जाता है। इसके साथ ही पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चकवाल में स्थित कटासराज शिव मंदिर भी काफी पुराना है। यहां भारत-पाकिस्तान तनातनी की वजह से हिंदुओं की पहुंच न के बराबर है, जो बलूचिस्तान के बनने से यहां तक भारतीय हिंदू दर्शन करने जा सकेंगे। कटासराज शिव मंदिर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चकवाल जिले में स्थित है। यह मंदिर एक मंदिर-समूह का हिस्सा है, जिसमें कई अन्य छोटे मंदिर भी शामिल हैं। कटासराज मंदिर की विशेषता यहां स्थित पवित्र सरोवर है, जिसे कटास कुंड कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह सरोवर भगवान शिव के आंसुओं से बना है, जब उन्होंने अपनी पत्नी सती के वियोग में विलाप किया था।

कटासराज मंदिर प्राचीन काल में हिंदू धर्म के शिक्षा और दर्शन के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में जाना जाता था। कहा जाता है कि पांडव अपने वनवास के दौरान यहां कुछ समय रुके थे। यह भी माना जाता है कि महान दार्शनिक और विद्वान आदि शंकराचार्य ने यहां दर्शन का प्रचार-प्रसार किया था। कटासराज मंदिर परिसर का वास्तुशिल्प हिंदू-बौद्ध शैली का अद्भुत उदाहरण है। हालांकि, विभाजन के बाद इस मंदिर में पूजा कम हो गई। हालांकि, यह आज भी पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए एक तीर्थस्थल है।

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक कजोड़मल मीना के लिए स्काईटक प्रिन्टर्स, 111, नवाब कल्लन का बाग, एमएलए क्वार्टर, नीयर समाचार जगत, एमआई रोड, जयपुर से मुद्रित एवं 303, भव्य टॉवर, कबीर मार्ग, बनीपार्क जयपुर से प्रकाशित।
(इस अंक में प्रकाशित समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पीआरबी एक्ट के तहत उत्तरदायी) समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर शहर होगा। मो. नं. 9928078717